News सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-86
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

इंदौर, सोमवार, 01 जुलाई 2024

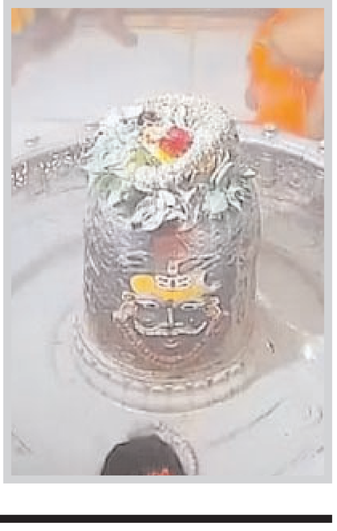

आज का विचार

सफलता मन की एक अवस्था है यदि आप सफलता चाहते हैं, तो सफलता के रूप में अपने बारे में सोचना शुरू करें

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

मप्र और राजस्थान के लिए अहम कामः दोनों राज्यों की पानी की दिक्कत होगी खत्म, 30 लाख किसानों को फायदा मिलेगा

पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदियों को जोड़ने का काम शुरू

सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रखी दो दशक पुराने प्रोजेक्ट की आधारशिला

भोपाल। मध्यप्रदेश और राजस्थान के लिए रविवार का दिन अहम रहा। इस दिन राजधानी भोपाल में पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया। एमपी के सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने परियोजना की आधारशिला रखी। इससे पहले पार्वती- कालीसिंध-चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। मध्यप्रदेश और राजस्थान की नदियों को जोड़ने की यह परियोजना कुल 72 हजार करोड़ की है। इससे दोनों राज्यों में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। योजना में 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। परियोजना से मध्यप्रदेश के मालवा और चंबल इलाके के कुल 13 जिले लाभान्वित होंगे। इसी तरह राजस्थान के भी 13 जिलों में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इस मौके पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बहुत बड़ी योजना है। मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों प्रदेशों में सिचांई के लिए यह लाभदायक साबित होगी।

20 साल से अटका था प्रोजेक्ट सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पार्वती काली सिंध चम्बल परियोजना 20 साल से अटकी थी पर हमने छोटे छोटे विवादों से परे राज्यों के हित में फैसला लिया। श्योपुर, मुरैना ,ग्वालियर, गुना, चम्बल के लोग पानी की दिक्कत से जूझते हैं,

लेकिन इस परियोजना से प्रदेश के 13 जिले पानी की परेशानी से मुक्त हो जाएंगे।

72 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट यह परियोजना कुल 72 हजार करोड़ रुपए की है। एमपी सरकार 35 हजार करोड़ और राजस्थान सरकार 37 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। परियोजना से कुल 6.17 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। एमपी की 3.37 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी जिससे 30 लाख किसानों को फायदा होगा।

साकार हो रहा अटलजी का सपना जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा 2004 से पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना लंबित पड़ी थी। आज दो व्यक्तियों के प्रयासों और सोच, समन्वय से यह सौगात एमपी, राजस्थान को मिल रही है। 2003-04 में मध्यप्रदेश की सिंचाई का रकबा मात्र 6-7 लाख हेक्टेयर होता था। मोहन यादव के नेतृत्व में आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं 2025 में हमारा लक्ष्य लगभग 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई करेंगे।

सिंगल कॉलम

आज से शुरू होगा मप्र विधानसभा का मानसून सत्र, 3 जुलाई को बजट

भोपाल। सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का 19 दिवसीय मानसून सत्र प्रारंभ होगा। इसके हंगामेदार होने के आसार हैं। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए नर्सिंग कॉलेज, चुनाव के समय की घोषणाओं को पूरा न करने, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के साथ हुई अत्याचार की घटनाओं को प्रमुखता से उठाने की तैयारी की है। वहीं, सत्तारूढ़ दल भाजपा ने भी पलटवार की तैयारी की है। सभी मंत्रियों से कहा गया है कि वे विभागीय उपलब्धियों के साथ कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन को आधार बनाकर अपनी बात दमदारी से रखें। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट तीन जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि पूर्व से संचालित किसी भी योजना का बंद नहीं किया जाएगा। बजट में लाड़ली बहना, लाड़ली लक्ष्मी, गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस, पशुपालकों को पांच रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि, रसोई गैस 450 रुपये में देने अनुदान, किसानों को शून्य प्रतिशत पर कृषि ऋण, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजनाओं में अनुदान, सिंहस्थ और अधोसंरचना विकास से जुड़े कामों के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रविधान किए जाएंगे।

कोहली-रोहित के बाद जडेजा ने भी लिया टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

नई दिल्ली। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद एक और भारतीय दिग्गज ने टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस दिग्गज का नाम है रविंद्र जडेजा। बेहद शानदार ऑलराउंडर जडेजा ने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर इस बारे में जानकारी दी है। अपनी पोस्ट में जडेजा ने टी-20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि यह विश्वकप जीतना किसी सपने के सच होने जैसा था। गौरतलब है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले ही टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। विराट ने तो मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड लेते समय ही इसका ऐलान कर दिया था। वहीं, रोहित ने बाद में प्रेस कांफ्रेंस में संन्यास की घोषणा की। इंस्टाग्राम पर लिखी पोस्ट में जडेजा ने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने लिखा है कि कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मैं टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करता हूं। मैंने अपने देश के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब अन्य फॉर्मेट्स में भी मेरा यह योगदान लगातार जारी रहेगा। जडेजा ने लिखा कि टी-20 विश्वकप जीतना एक सपने के सच होने जैसा था। यह मेरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का चरम है। इसके साथ ही दिग्गज ऑलराउंडर ने समर्थकों और प्रशंसकों का आभार भी जताया है। जडेजा ने लिखा है कि बेहतरीन यादों, तारीफों और लगातार समर्थन के लिए आप सभी का शुक्रिया।

वॉरेन बफे ने एक बार फिर बदली वसीयत, गेट्स फाउंडेशन से पीछे खींचे हाथ

वॉशिंगटन। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। 93 साल के हो चुके बफे ने अपनी वसीयत में बदलाव करके सुर्खियां बंटोर ली हैं। उन्होंने खुलासा किया कि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति का हकदार कौन होगा। उनका कहना है कि उनकी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान जारी रखने की कोई योजना नहीं है। इसके बजाय वे एक नया चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे, जिसे उनके तीन बच्चे चलाएंगे। बफे का कहना है कि गेट्स फाउंडेशन को उनके मरने के बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वे कई बार अपनी वसीयत को बदल चुके हैं और इसमें एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब उनकी दौलत एक नए ट्रस्ट को मिलेगी, जिसे उनके तीन बच्चे चलाएंगे। बफे के सभी बच्चों की अपनी-अपनी चैरिटेबल संस्था है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। साथ ही पूरा भरोसा है कि वे मेरी विरासत को सही ढंग से आगे बढ़ाएंगे। गौरतलब है, इससे पहले बफे ने कहा था कि उनकी दौलत को 99 फीसदी से अधिक हिस्सा उनके परिवार से जुड़े चार ट्रस्टों और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 129 अरब डॉलर यानी करीब 1,07,54,00,11,50,000 रुपए है और वे दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने कहा कि बफे करीब 9000 क्लास ए शेयरों को 1.3 करोड़ से अधिक क्लास बी शेयरों में बदल रहे हैं। इसमें से 93 लाख शेयर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को जाएंगे। बाकी शेयर बफे के परिवार से जुड़े ट्रस्टों को बांटे जाएंगे।

एहतियातः पेपर लीक होने के बाद बड़ा कदम उठाने जा रही सरकार, हो चुकी तीन उच्च-स्तरीय बैठकें, धर्मेंद्र प्रधान बोले- पेपर लीक की नहीं होगी गुंजाइश, तैयार होगा फुल प्रूफ प्लान

अगले साल से ऑनलाइन मोड में नीट-यूजी!

नई दिल्ली। नीट-यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद कई तरह के सवाल उठे हैं। इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और संसद के गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। नीट यूजी पेपर लीक पर बढ़ते विवाद के बीच सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल से नीट-यूजी का एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराए जाने पर विचार चल रहा है। मालूम हो कि अब तक नीट की परीक्षा पेन-एंड-पेपर से होती रही है, जिसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मगर, आने वाले दिनों में नीट यूजी के लिए भी आईआईटी जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड जैसी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा को अपनाया जा सकता है। नीट पेपर लीक को लेकर बीते हफ्ते में करीब तीन उच्च-स्तरीय बैठकें हुई हैं, जहां मामले को लेकर अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 22 जून को केंद्र सरकार की ओर से इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। टेस्ट प्रक्रिया व डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधारों की सिफारिश करने और परीक्षा एजेंसी एनटीए की संरचना व कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए यह कमेटी बनाई गई। गौरतलब है कि 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 2019 से नीट ऑनलाइन और साल में दो बार आयोजित की जाएगी। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय की आपत्ति के बाद शिक्षा मंत्रालय को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। मगर, अब सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

स्थगित परीक्षाएं अब कम्प्यूटर आधारित टेस्ट मोड में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट विवाद के चलते स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखें जारी कर दी हैं। ज्वॉइंट सीएसआईआर यूजीसी-नेट अब 25 से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। वहीं, स्थगित यूजीसी नेट की परीक्षा 21 अगस्त से 8 सितंबर के बीच होगी। इस साल बड़ा बदलाव यह है कि ये परीक्षाएं कम्प्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएंगी। ऐसे में अबकी बार कलम-और-कागज का इस्तेमाल नहीं होगा। बता दें कि एनटीए की ओर से आयोजित नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (एनसीईटी) 10 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।

नीट पीजी की तारीख आज-कल में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) आगामी नीट पीजी परीक्षा को रिशेड्यूल करने की तैयारी में है। इसे लेकर नई तारीखों की घोषणा सोमवार या मंगलवार को हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनबीई अगले दो दिन के भीतर नीट-पीजी के लिए नई तारीख का ऐलान करेगा। दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद काफी बढ़ा हुआ है। एहतियाती कदम उठाते हुए पिछले सप्ताह रद्द की गई परीक्षाओं में नीट-पीजी की परीक्षा भी शामिल है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया सरकार का प्लान राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं समेत अन्य सभी परीक्षाओं की निष्पक्षता को लेकर कुछ दिनों से उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा दावा किया किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि केंद्र सरकार अब ऐसी व्यवस्था करेगी कि भविष्य में किसी भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पेपर लीक जैसी स्थिति की आशंका ही न हो। मंत्री ने कहा कि तकनीकी और साइबर आपराधिक चुनौतियों के बीच सरकार अब नए प्लान पर काम करेगी, जिसके तहत पेपर लीक की आशंका शून्य हों। पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार केंद्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द की गई। इसको लेकर एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक टेस्ट रद्द हुआ है, दूसरा टाल दिया गया है।

नए विवाद में घिरे सीहोर के कथा वाचक

पंडित प्रदीप मिश्रा पर अब मां ताप्ती के अपमान का आरोप

मुलताई। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधारानी के विवादित बयान पर शनिवार को बरसाने में माफी मांगी ही थी कि रविवार को फिर से एक नया विवाद शुरू हो गया। ताप्ती नदी से जुड़े एक बयान को लेकर अब उनका विरोध हो रहा है। मुलताई स्थित ताप्ती मंदिर के पुजारी सौरभ जोशी ने कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा माफी मांगे। दरअसल, मुलताई स्थित ताप्ती मंदिर के पुजारी सौरभ जोशी ने एक वीडियो जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा में बताया है कि ताप्ती महारानी भागवान कृष्ण पर मोहित हो गईं थीं, जिस कारण यमुना ने उन्हें श्राप दिया था। जबकि इस बात का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। बता दें कि दिसंबर 2022 में पंडित प्रदीप मिश्रा बैतूल में शिवपुराण की कथा के लिए गए थे। तभी का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में वे कह रहे हैं कि माता यमुना और ताप्ती दोनों बहनें हैं, लेकिन आपस में उनकी कभी नहीं बनी। घाट पर भगवान जब रास करते थे, उस समय यमुनाजी उनके विग्रह पर आए पसीने को पोंछने के लिए जाती थीं, लेकिन एक बार यमुना का रूप धारण कर ताप्ती चली गईं। ताप्ती ने श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया, लेकिन जैसे ही यमुनाजी ने वहां ताप्ती को देखा उन्हें गुस्सा आ गया। पूछने पर ताप्ती ने बताया कि मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूं। इस पर यमुना ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि किसी भी नदी में अस्थियां विसर्जित होंगी तो उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, लेकिन तेरे जल में वह तुरंत गल जाएंगी। यही कारण है कि ताप्ती नदी में आज भी अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, जो डेढ़ घंटे में गल जाती हैं।

क्षमा याचना करें प्रदीप मिश्रा वीडियो जारी करते हुए सौरभ जोशी ने कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मां ताप्ती इस प्रकार कभी भी श्री कृष्ण पर मोहित नहीं रहीं। ताप्ती के जल में अस्थियां उनकी महिमा की वजह से जल्द घुलती हैं। जोशी ने कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा मुलताई आकर ताप्ती में जल आचमन कर क्षमा याचना करें। गौरतलब है कि राधारानी पर दिए विवादित बयान को लेकर प्रदीप मिश्रा ने बरसाना जाकर नाक रगड़ कर माफी मांगी है। अब फिर एक विवाद सामने आ गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

स्पीकर के बाद अब डिप्टी स्पीकर पद के लिए घमासान

अयोध्या सांसद पर दांव लगा सकता है विपक्ष

नई दिल्ली। पहले लोकसभा स्पीकर को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में घमासान देखने को मिला था। अब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए भी विपक्षी दलों ने दावेदारी तेज कर दी है। इंडिया ब्लॉक, लोकसभा उपाध्यक्ष पद के लिए फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को कैंडिडेट घोषित करने का प्लान बना रही है। इस गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं। 78 वर्षीय अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं और अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट से जीतकर आए हैं। पहले खबरें थीं कि कांग्रेस केरल से आठ बार के सांसद के. सुरेश को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहती है। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। अन्य सहयोगियों से भी इस पर बात की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाने का विचार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी का था। उन्होंने यह बात अपने भतीजे अभिषेक से कही। तीनों दलों को लगता है कि फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद एक अलग तरह के कैंडिडेट होंगे और उनकी उम्मीदवारी एक मजबूत संदेश देगी। वे 50,000 से अधिक मतों से जीते हैं।

आम सहमति बनाई जा रही राहुल गांधी और अखिलेश यादव से बातचीत में, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उपाध्यक्ष पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का चयन एक मजबूत संदेश देना चाहिए।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री के बेटे पर फायरिंग...तलवार मारी

ग्वालियर। ग्वालियर में रविवार दोपहर भाजपा के प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह गुर्जर के बेटे पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की। आवाज सुनकर परिजन और दूसरे लोग वहां आ गए। उन्होंने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान बदमाश अपनी लाइसेंसी राइफल छोड़कर भाग गए। जाते-जाते एक हमलावर ने बीजेपी नेता के बेटे को तलवार मार दी। जिससे वो घायल हो गया। घटना दोपहर करीब 3 बजे सात नंबर चौराहा सीपी कॉलोनी मुरार की है। भाजपा नेता ज्ञान सिंह ने मुरैना के रहने वाले संदीप मावई पर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लोन को लेकर उसके भांजे से संदीप का विवाद है। ज्ञान सिंह गुर्जर भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। उनके दो बेटे लव गुर्जर और पुष्पेंद्र गुर्जर हैं। उन्होंने बताया- रविवार दोपहर करीब 3 बजे लव गुर्जर को उसके मामा के बेटे अनुज गुर्जर का कॉल आया था। जिसके बाद लव घर के बाहर खड़ा हो गया। इस बीच, वहां कार से संदीप मावई (गुर्जर) चार से पांच अन्य साथियों के साथ आया। गाली-गलौज करते हुए राइफल से फायर कर दिया। लव ने नीचे झुक कर जान बचाई। इसके बाद बाद हमलावरों ने एक और फायर किया। गोलियों की आवाज सुनकर लव का छोटा भाई पुष्पेंद्र गुर्जर बाहर आया। वह हमलावरों से भिड़ गया। मदद के लिए आसपास के अन्य लोग भी आ गए। घबराकर बदमाश भागने लगे, लेकिन हड़बड़ाहट में राइफल छोड़कर भाग गए। भागते समय हमलावरों ने पुष्पेन्द्र पर तलवार से हमला कर दिया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में नाकाबंदी कर दी है।

सिंगल कॉलम

पिता ने की दूसरी शादी, नाराज बेटे ने चाकू घोंपकर की हत्या

इंदौर। इंदौर में फिर एक हत्या हो गई। एक युवक अमन सिंह ने अपने ही पिता कमल पिता धन सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी। अमन अपने पिता की दूसरी शादी से था नाराज। आए दिन घर खर्च को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होती थी। हत्या के पहले भी पिता और पुत्र के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद उसने किचन में रखा चाकू पिता के पेट में घोंप दिया। घायल अवस्था में परिजन कमल को अस्पताल लेकर गए, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के कुंदन नगर की है। कमल की पहली पत्नी का निधन हो गया था। पहली पत्नी से दो बेट और दो बेटियां है। चारों का विवाह हो चुका था। कमल अपने बड़े बेटे अमन के साथ रहता था। कमल ने सालभर पहले दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद परिवार का खर्च और बढ़ गया था। इससे बेटा अमन नाराज था । इस बात को लेकर अक्सर दोनों में विवाद होता था। कमल की दूसरी पत्नी निशा से भी अमन की पत्नी की अनबन चलती रहती थी। शुक्रवार को भी चारों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद अमन ने चाकू से पिता पर वार कर दिया और वह फरार हो गया। मामले में राजेंद्र नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी अमन की तलाश शुरू कर दी है।

अब नगर निगम में 31 जुलाई तक भर सकेंगे टैक्स

इंदौर। शहर के निगम के सभी जोन ऑफिस और मुख्यालय में 30 जून को सुबह 9 से रात 8 बजे तक सम्पत्ति कर में 6.25त्न और जल कर में 6त्न की अग्रिम छूट का लाभ शुरू किया था। दोपहर को पोर्टल धीरे चलने और फिर टेक्निकल खराबी आने से तारीख आगे बढ़ा दी गई है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि अब लोग 31 जुलाई तक छूट का लाभ ले सकते हैं। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की अग्रिम सम्पत्ति कर और जल कर राशि का भुगतान करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए यह सुविधा दी गई है। करदाता सम्पत्ति कर, जल कर और कचरा संग्रहण शुल्क की राशि का भुगतान संबंधित जोन ऑफिस या निगम मुख्यालय में जमा करा सकते हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अग्रिम छूट का लाभ लें और शहर के विकास में सहयोग करें।

गर्ल्स और बॉयज होस्टल के संचालकों में विवाद, केस दर्ज

इंदौर। इंदौर के भंवरकुआ में गर्ल्स और बॉयज होस्टल के संचालकों के बीच विवाद हो गया। इसमें दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। भंवरकुआ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंगल नगर में शिवम शर्मा का सत्कार गर्ल्स होस्टल हैं। इनके सामने मेपल बॉयज होस्टल है। शिवम वर्मा का आरोप है कि यहां कुछ लड़के हंगामा कर रहे थे। इस पर वह समझाने पहुंचे तो होस्टल के वार्डन प्रहर्श शर्मा ने, विनीत, आदित्य, पुष्पेन्द्र, मोक्ष और गजेन्द्र दांगी के साथ मिलकर मारपीट की। उन्हें धमकाया। उनका बचाव करने आए विक्की सुकेन्द्र और नीरज के साथ मारपीट की और होस्टल की वार्डन और अन्य लड़कियों को भी धमकाया। इधर प्रहर्श शर्मा ने भी शिवम शर्मा, रोहित शर्मा, सुवेन्द्र और विक्की के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रहर्श ने बताया कि वह मेपल होस्टल के संचालक हैं। आरोपी उनके होस्टल का वीडियो बना रहे थे। उन्होंने रोका तो आरोपियों ने धमकी दी। इस दौरान समझाया तो लात घूंसे और डंडों से मारपीट कर धमकाया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है।

ब्लेड मारकर कंपनी कर्मचारी से लूटे 1.10 लाख रुपए

इंदौर। इंदौर के लसूड़िया इलाके में शनिवार को ऑनलाइन कंपनी के एक कर्मचारी को बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट लिया। पीड़ित शनिवार रात में थाने पहुंचा। यहां पर स्टाफ के चेकिंग में होने के चलते शिकायती आवेदन लेकर रवाना कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया। घटना वेयर हाउस रोड की है। यहां लक्ष्मी पेट्रोल पंप के नजदीक अमेजन कंपनी के कलेक्शन एजेंट सुजल मालवीय निवासी स्कीम नंबर 78 के साथ लूट की वारदात हो गई। बताया जाता है कि रात में बारिश होने के चलते वह शनिवार रात करीब 11 बजे कलेक्शन के रुपए जमा करने पहुंचा था। इस कंपनी के वेयर हाउस से करीब 300 मीटर की दूरी पर बाइक पर दो बदमाशों ने उसे रोका और बायपास का रास्ता पूछा। एक बदमाश ने ब्लेड से सुजल के गले और हाथ पर वार कर दिया। वह खुद को संभालने लगा तो दोनों बदमाश कलेक्शन के रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। सुजल ने आरोपियों को पकड़ने मदद दौड़ लगाई, लेकिन वे हाथ नहीं आए। थाने पर स्टाफ नहीं, चैकिंग चल रही है घटना की रिपोर्ट लिखाने सुजल उसी समय लसूड़िया थाने पहुंचा। यहां पुलिसकर्मियों ने कहा कि स्टाफ चैकिंग पर है, कॉम्बिंग गश्त भी चल रही है।

अब धार की भोजशाला पर जैन समाज का दावा

खुदाई में निकली थी मूर्तियां, कोर्ट में लगी याचिका

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। धार में एएसआई के सर्वे के बाद हाईकोर्ट में अब जैन समाज ने याचिका लगाई है। एएसआई द्वारा भोजशाला में की गई खुदाई के दौरान जैन तीर्थंकर मूर्तियां भी निकली। इसके बाद जैन समाज ने भोजशााला पर दावा पेश किया है। समाज ने याचिका में कहा है कि धार में जैन गुरुकुल था, जिसे भोजशाला कहा जा रहा है। हाईकोर्ट ने जैन समाज की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली है।

हाईकोर्ट के निर्देश पर डेढ़ माह तक धार की भोजशाला में सर्वे चला। खुदाई कर भोजशाला की पुरानी बनावट, निर्माण शैली और धार्मिक चिन्हों की जानकारी जुटाई गई। इस बीच, जैन समाज ने याचिका लगाई। इसमें कहा गया है कि भोजशाला में जैन धर्म से संबंधित अंबिका देवी और सरस्वती देवी की मूर्ति के अलावा भोजशाला में जैन गुरुकुल होने के प्रमाण मिले हैं। जैन समाज के शिलालेख ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित हैं।

उधर, हिंदू पक्ष पूर्व में भोजशाला पर अपना अधिकार जता चुका है। समाज ने कहा कि वहां सरस्वती माता का मंदिर था और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था।

विश्व जैन संगठन के मीडिया प्रभारी राजेश जैन दादू ने बताया कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील दिनेश कुमार जैन समाज की तरफ से पक्ष रखेंगे। हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि सुनवाई में हमारे समाज के दो लोगों को भी शामिल किया जाए। याचिका पर **अगले सप्ताह सुनवाई होगी।**

मूर्तियां जैन समाज को सौंपी जाएं

याचिका में कहा है कि अब तक भोजशाला मामले में चल रही सुनवाई में सिर्फ दो ही पक्षकार (सनातनी और मुस्लिम) हैं, लेकिन अब जैन समाज को भी सुना जाए। इसके लिए सुनवाई के दौरान जैन समाज के दो प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। संगठन की इंदौर शाखा के अध्यक्ष मयंक जैन और मीडिया प्रभारी राजेश जैन दद्दू ने बताया कि हमने यह मांग भी रखी है कि खोदाई के दौरान जैन समाज से जुड़ी मूर्तियों को समाज को सौंपा जाए, जिससे इन मूर्तियों को सही स्थान पर विराजित किया जा सके।

एएसआई 2 जुलाई को पेश कर सकता है रिपोर्ट

हाईकोर्ट के निर्देश पर धार में 22 मार्च को सर्वे शुरू हुआ था, जो 98 दिन चला। एएसआई दो जुलाई को अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। एएसआई सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि भी भोजशाला में मौजूद रहते थे।

कटे हुए पेड़ों को दी श्रद्धांजली, बचे हुए पेड़ों को बांधे रक्षासूत्र

पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए लोग

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है और हरियाली को बचाने के लिए अब लोग एकजुट होने लगे हैं। मल्हार आश्रम से रविवार को प्रकृति संरक्षण के लिए नया शंखनाद हुआ और सभी ने शपथ ली कि अब अहिल्या की इस नगरी में पेड़ों की कटाई किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। सभी ने एक सुर में कहा कि अब इंदौर में जहां पर भी पेड़ कटेंगे हम उन्हें बचाने के लिए जाएंगे।

सुबह 8 बजे मल्हार आश्रम स्कूल के गेट पर शहरवासियों ने जुटना शुरू किया। मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार और प्रशासन को सच्चाई दिखाने के लिए आधे घंटे तक बैनर, पोस्टर लेकर खड़े रहे। आंदोलन में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा और हर वर्ग की सहभागिता दिखी। सभी ने हस्ताक्षर किए और शपथ ली कि पेड़ों की कटाई अब नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद सभी कतारबद्ध होकर कटे हुए पेड़ों के पास गए। मल्हार आश्रम के पिछले हिस्से में बड़ी संख्या में कटे हुए पेड़ पड़े हैं। वहां पर जाकर सभी ने मृत पेड़ों की श्रद्धांजली दी।

प्रकृति को बचाने के लिए जुटे प्रबुद्धजन

पीथमपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम कोठारी, जनहित पार्टी के अभय जैन, शिक्षाविद् एसएन गर्ग, पर्यावरणविद ओपी जोशी, वाइल्ड वॉरियर्स संस्था के सचिन मतकर, यूथ होस्टल के अशोक गोलाने, द नेचर संस्था के ओपी माहेश्वरी, अभ्यास मंडल के सदस्य, कलमकर प्रकृति संस्था के श्रीकांत, समाजसेवी किशोर कोडवानी, समर्थ मठ संस्था के अशोक पाटनकर, आई आई डी संस्था के अखिलेश जैन, ग्राहक पंचायत समिति के गोपाल साहू, मल्हार आश्रम के भूतपूर्व छात्र चमन पाटिल एवं संदीप खानवलकर तथा अजय लागू, हरी ओम ग्रुप मल्हार आश्रम के नरेश यादव, मल्हार एरोबिक्स ग्रुप के मेघा लोखंडे, पूर्व पार्षद दीपिका कमलेश नाचन, पंतवैध्य कॉलोनी रहवासी संघ अध्यक्ष रजनी जोशी, नारायण बाग कॉलोनी रहवासी संघ अध्यक्ष मीनाक्षी जठार, स्वप्निल व्यास, श्याम सुन्दर यादव, संस्था रूपांकन, संस्था अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन, अशोक दुबे, दिलीप वाघेला, प्रोफेसर भोलेश्वर दुबे मौजूद रहे।

कई कॉलोनियों के रहवासी जुटे

इसके साथ कई अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी, खेल संगठनों के पदाधिकारी, रामबाग, तिलक पथ, गणेश कॉलोनी, जति कॉलोनी, पंतवैध्य कॉलोनी, नारायण बाग कॉलोनी के रहवासी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इसके साथ कई अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी, खेल संगठनों के पदाधिकारी, रामबाग, तिलक पथ, गणेश कॉलोनी, जति कॉलोनी, पंतवैध्य कॉलोनी, नारायण बाग कॉलोनी के रहवासी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

देवी अहिल्या विवि के 80 कॉलेज आज से होंगे टंट्या भील यूनिवर्सिटी के

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से अलग होकर 80 कॉलेज खरगोन में नई यूनिवर्सिटी से जुड़ गए हैं। इन कॉलेजों की क्रांतिसूर्य टंट्या भील यूनिवर्सिटी खरगोन से जुड़ने की शुरूआत 1 जुलाई 2024 के फर्स्ट ईयर से होने जा रही है। इसी के साथ सभी कॉलेज ऑफिशियल तौर पर खरगोन यूनिर्वसिटी से जुड़ जाएंगे। डीएवीवी से कॉलेज अलग होने का असर अगले साल मार्च के बजट में दिखेगा। विवि का अगला बजट 350 करोड़ से काफी घटेगा। क्योंकि अब 80 कॉलेज दायरे से बाहर हो गए हैं। वहीं इस साल 2024 में 14 करोड़ संबद्धता शुल्क और 3 करोड़ एग्जाम शुल्क नहीं आएगा। क्योंकि अब यह शुल्क खरगोन विवि के पास जाएगा।

आर्थिक, एकेडमिक बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर और अलीराजपुर जिलों के कॉलेज डीएवीवी के दायरे से बाहर होंगे। हालांकि पुराने सभी 70 हजार छात्रों की बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए और बीसीए जैसे यूजी सेकंड और फाइनल ईयर की परीक्षा डीएवीवी ही आयोजित करेगी। जबकि पीजी में एमकॉम, एमए, एमएससी और अन्य पीजी कोर्स की थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा डीएवीवी लेगी। इन सभी छात्रों की पूरक परीक्षा, रिव्यू और मार्कशीट, डिग्री तक का जिम्मा डीएवीवी का रहेगा। नई यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी डीएवीवी के दायरे में अब भी सवा दो सौ से ज्यादा कॉलेज हैं।

आर्थिक नुकसान होगा

डीएवीवी को करीब 18 करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा। करीब 15 करोड़ रुपए का घाटा इन कॉलेजों के संबद्धता शुल्क से होगा। हर साल यह शुल्क डीएवीवी के पास जमा होता था। वहीं करीब 3 करोड़ का नुकसान डीएवीवी को परीक्षा शुल्क से होगा। 70 हजार पुराने छात्र डीएवीवी के दायरे में बने रहेंगे। 80 कॉलेज अब खरगोन यूनिवर्सिटी में 2024 का संबद्धता शुल्क जमा कराएंगे।

इंदौर में बीती रात हुई हत्या

पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में

प्रदीप चौधरी । सिटी चीफ इंदौर- इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में बीती रात नशे में कुछ युवकों के बीच में हुआ विवाद.... सुनील चौहान नाम के लड़के को जांघों पर आई चोट...अस्पताल ले जाते रास्ते में हुई मौत.. पुलिस पहुंची घटना स्थल पर.....

पुलिस द्वारा की गई आस पास पूछताछ.. मृतक के भाई और बहन के अनुसार दो लड़कों और एक लड़की को घटना स्थल से भागते हुए देखा गया... पुलिस कर रही घटना के कारणों की जांच। क्या यह लड़की को लेकर विवाद था या कुछ और ?

.....बताया जा रहा है कि मृतक पर दर्ज थे कई अपराध। पुलिस को आरोपियों की तलाश।

गर्मी में बिजली की खपत 40 फीसदी तक बढ़ी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। जून माह में नागरिकों के घरों में बिजली बिल पहुंचने के बाद शिकायतें भी बढ़ गई है। ज्यादातर उपभोक्ता बिजली कंपनी पर अधिक बिल भेजने की शिकायत कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को संदेह है कि बिजली कंपनी ने टैरिफ दरें बढ़ा दी है या फिर गलती से ज्यादा बिल जारी किए हैं। हालांकि बिजली कंपनी इसे लंबे चले गर्मी के मौसम और बढ़ी हुई खपत का असर बता रही है। जून माह में लोगों के घरों में पहुंचे बिजली बिल आम तौर पर हर माह में आने वाले बिल से डेढ़ से दो गुना है। तमाम छोटे-बड़े उपभोक्ता इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। बिलों में सुधार के आवेदन भी लगातार बिजली कंपनी के जोनों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि, जोनों से बिल सुधार के अधिकार छिन लिए हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं के बिलों में सुधार भी नहीं हो रहा। बिजली कंपनी के अनुसार बीते अप्रैल से जून तक लगातार शहर में तेज गर्मी का प्रभाव रहा। आम तौर पर शहर की बिजली मांग बीते वर्षों में गर्मियों में छह से सवा छह सौ मैगावाट तक होती थी। इस साल सवा सात सौ मैगावाट के पार बिजली की मांग पहुंच गई।

बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री (शहर वृत्त) मनोज शर्मा के अनुसार देखा जाए तो औसत वृद्धि 30 से 40 प्रतिशत हुई है। जबकि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि गर्मियों में बिजली खपत में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, इस अनुमान से कहीं ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई। बरसात शुरू हो चुकी है ऐसे में भी इंदौर में बिजली की मांग 600 मैगावाट के आसपास बनी हुई है।

अभी मिला है मई माह का बिल

बिजली कंपनी के अनुसार जून माह में जारी हुए बिजली के बिल मई माह की खपत के हैं। मई माह बिजली खपत के लिहाज से सबसे ज्यादा मांग वाला महीना था। तेज गर्मी के कारण लोगों के यहां बिजली का उपभोग 30 से 40 प्रतिशत बढ़ा। उस माह के बिल अब लोगों को मिले हैं, तो उन्हें बढ़ी खपत के कारण राशि भी ज्यादा लग रही है। बिजली कंपनी के अनुसार उपभोक्ता अपने मीटर में खपत जांच लें। अगर, बिल की रीडिंग से असल मीटर रीडिंग अलग है, तो वो इस बारे में शिकायत कर सकता है। देखा जा रहा है कि इस साल लंबी गर्मियां चलने और अधिक तापमान लगातार रहने से खपत बढ़ी है। बाजार से रिकॉर्ड एयर कंडीशन बिकने की खबरें भी आई हैं। ऐसे में बढ़ी राशि के बिल आना स्वभाविक है।

अगले माह भी आएगा भारी-भरकम बिल

जून माह के आखिर में शहर में बरसात का असर देखने को मिला है। इससे पहले इस महीने में गर्मी का प्रकोप बना रहा। ऐसे में विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले एक माह आने वाला बिजली का बिल भी भारी-भरकम होगा। ज्यादातर घरों में एसी-कूलर और पंखे पूरे समय चलते रहे। लिहाजा जुलाई में भी बिजली का बढ़ा हुआ बिल लोगों को झटका दे सकता है।

इंदौर में जून में हुई 2 इंच कम बारिश

इंदौर। इंदौर में रविवार दोपहर बाद कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। शहर के पूर्वी और पश्चिमी इलाके में अचानक बादल छाने के साथ तेज हवा का दौर शुरू हो गया। इस दौरान कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी तो कई हिस्सों में तेज बारिश होती रही है। दरअसल, शनिवार शाम को हुई तेज बारिश ने शहर को तर करने की शुरूआत कर दी थी। पिछले 24 घंटों में आधा इंच से ज्यादा बारिश हुई है। इस सीजन में अब तक 4 इंच बारिश हुई है जबकि जून को कोटा 6 इंच का है। इस तरह अभी 2 इंच पानी की और दरकार है जबकि रविवार को माह का अंतिम दिन था। हालांकि इस बार जून की बारिश ने पिछले साल की बराबरी कर ली है। पिछले साल 4 इंच बारिश हुई थी। शनिवार को सुबह से ही बादल छाए थे और फिर दिन में कुछ देर के लिए धूप निकली। इसके बाद फिर बादल छा गए। फिर शाम को हुई तेज बारिश ने तो मौसम में ठण्डक घोल दी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी सौराष्ट्र में कच्छ में सर्कुलेशन बना हुआ है। एक लो प्रेशर एरिया उड़ीसा और आसपास भी है। इसके साथ ही बंगाल

की खाडी में सिस्टम बना हुआ है। इनके सहित कई छोटे-छोटे सिस्टम्स बने हैं। देश में 90त्न हिस्सों में मानसून एक्टिव है। इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में अभी बादलों के छाने, गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। शाजापुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा शाजापुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। यहां दिन का तापमान 25.4 डिग्री रहा, जबकि रात में 22.4 डिग्री दर्ज किया गया था। पचमढ़ी, उमरिया, नौगांव, मलाजखंड, सागर और सिवनी में पारा 30 डिग्री से कम रहा। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 30.2 डिग्री, इंदौर में 31.6 डिग्री, ग्वालियर में 34.6 डिग्री, जबलपुर में 30.5 डिग्री और उज्जैन में पारा 32.2 डिग्री दर्ज किया गया।

आधी रात को तिरंगा लेकर कार की छत पर सवार हुए सारंग, नियमों की उड़ाईं धज्जियां

टी-20 वर्ल्डकप जीत की खुशी में मंत्री ने दिखाया स्टंट

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। टी20 विश्वकप में भारतीय टीम की जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। इस बीच मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी टीम इंडिया की जीत का जश्न में झूमते नजर आए। बाद में भारत की जीत में मंत्रीजी इस कदर डूब गए स्टंटबाजी करने लगे। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंत्री विश्वास सांरग की कार तेफ रफ्तार में सड़क पर दौड़ती नजर आ रही है और वह तिरंगा थामे कार की छत पर बैठे हैं। इस दौरान उनके साथी

भी कार पर लटके नजर आए और पीछे बैंड बाजे की आवाज सुनाई दे रही है। इसे लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि हम सभी इस उम्मीद से मैच देख रहे हैं

कि भारत जीतेगा। टी20 वर्ल्ड कप भारत आएगा। सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं, बल्कि 130 करोड़ भारतीय भी खेल रहे हैं।

मध्य प्रदेश विधानसभा में आज शुरू होने वाले मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, 3 जुलाई को पेश होगा बजट

नर्सिंग कॉलेज घोटाला, वादाखिलाफी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

सिटी चीफ भोपाल।
मध्य प्रदेश विधानसभा का 19 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से प्रारंभ होगा। इसके हंगामेदार होने के आसार हैं। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए नर्सिंग कालेज, चुनाव के समय की घोषणाओं को पूरा न करने, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के साथ हुई अत्याचार की घटनाओं को प्रमुखता से उठाने की तैयारी की है। वहीं, सत्तारूढ़ दल भाजपा ने भी पलटवार की तैयारी की है। सभी मंत्रियों से कहा गया है कि वे विभागीय उपलब्धियों के साथ कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन को आधार बनाकर अपनी बात दमदारी से रखें। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट तीन जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकार ने तय किया है कि पूर्व से संचालित किसी भी योजना का बंद नहीं किया जाएगा। बजट में लाड़ली बहना, लाड़ली लक्ष्मी, गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस, पशुपालकों को पांच रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि, रसोई गैस 450 रुपये में देने अनुदान, किसानों को शून्य प्रतिशत पर कृषि ऋण, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार

योजनाओं में अनुदान, सिंहस्थ और अधोसंरचना विकास से जुड़े कामों के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रविधान किए जाएंगे। इसके अलावा गृह विभाग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता के लिए लोक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मध्य प्रदेश संशोधन, उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय संशोधन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगर पालिका अधिनियम, जेल विभाग बंदीगृह एवं सुधारात्मक सेवाएं और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खुले नलकूप में इंसानों की गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं से रोकथाम एवं सुरक्षा सहित अन्य विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।

भाजपा ने की पलटवार की तैयारी

कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए नर्सिंग कॉलेज घोटाले और विधानसभा चुनाव के समय किए गए वादों की पूर्ति न होने और कानून व्यवस्था की स्थिति को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी की है। इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया जा सकता है। इसे स्वीकार न करने की स्थिति में हंगामा होने के आसार हैं। वहीं, सत्तारूढ़ दल भाजपा ने पलटवार के लिए कांग्रेस सरकार में हुई गड़बड़ी को आधार बनाने की तैयारी की है। कमल नाथ सरकार के समय कालेजों को मिली अनुमतियों को सामने रखकर कांग्रेस को घेरा जाएगा।

2386 प्रश्न ऑनलाइन

विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों ने करीब 4187 सवाल पूछे हैं। इसमें से 2386 ऑनलाइन माध्यम से आए हैं। वहीं, 1901 ऑफलाइन सवाल पूछे गए हैं। विधानसभा सचिवालय कार्यवाही को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन करने पर जोर दे रहा है। ताकि कागज का कम से कम उपयोग हो।

कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और स्थानीय विकास के प्रश्न सबसे ज्यादा

विधानसभा सदस्यों ने मानसून सत्र के लिए कई प्रश्न पूछे हैं। सूत्रों के अनुसार सर्वाधिक प्रश्न कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और स्थानीय विकास से जुड़े हैं। कांग्रेस के सदस्यों ने विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणाओं, गेहूं, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, लाड़ली बहनों को तीन हजार रुपये देने, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं पर हुए अत्याचार, प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर अधिक विषयों पर सरकार से उत्तर मांगे हैं।

4 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम, तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं

प्रदेश में भारी बारिश का यलो और ऑरेंज अलर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में 4 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। कटऊ ने मध्य प्रदेश में तीन दिन भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने मंदसौर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, उज्जैन, चंबल संभागों के जिलों में कुछ जगहों पर जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर संभागों के जिलों में अनेक जगहों पर झमाझम बारिश हुई। सूबे के शहडोल, सागर संभागों के जिलों में विभिन्न जगहों पर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलीं। यही नहीं मध्य प्रदेश के अलिराजपुर, झाबुआ,

धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ आंधी पानी वाला मौसम रहा।

कल भी कई हिस्सों में झमाझम की चेतावनी

मौसम विभाग ने पहली और 2 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर मंदसौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सूबे के कई अन्य हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। भारतीय मौसम विभाग ने सूबे के विदिशा, बैतूल, ग्वालियर, दितया, भिंड, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

कार्य मंत्रणा समिति से रामनिवास रावत को हटाया

भोपाल। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कार्यमंत्रणा समिति से पूर्व मंत्री और विधायक रामनिवास रावत को हटा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश के बाद सचिवालय ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से रावत को हटाया। उनकी जगह दतिया से विधायक राजेंद्र भारती को समिति में जगह दी गई है। लोकसभा चुनाव के बीच में अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह, विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत और बीना से विधायक निर्मला सप्रे ने ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। कमलेश शाह ने भाजपा की सदस्यता के साथ ही विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने अभी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है।

सड़कों के गड्ढों की मोबाइल एप पर कर सकते हैं शिकायत, समय पर होगा काम

भोपाल। सड़क में अगर कहीं गड्ढा है और वो भरा नहीं जा रहा है, तो आम नागरिक मोबाइल एप से इसकी शिकायत कर सकेंगे। संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के पास यह पहुंचेगी और उसे निर्धारित समयसीमा में मरम्मत का काम पूरा करना होगा। इसकी सूचना भी शिकायतकर्ता को दी जाएगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग लोकपथ नाम से एप बना रहा है, जिसको लेकर विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें विभागीय मंत्री ने आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की और एप को शीघ्र ही कार्यान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि इस एप के माध्यम से आम नागरिक अपने मोबाइल से गड्ढों की जियोटेग फोटो खींचकर विभाग को सूचित कर सकेंगे। गड्ढों का फोटो जीपीएस लोकेशन के साथ संबंधित कार्यपालन यंत्री को प्राप्त होगा, जिससे गड्ढों की मरम्मत तेजी से और सही तरीके से की जा सकेगी।

सीयूईटी यूजी का परिणाम नहीं हुआ जारी

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) के यूटीडी में संचालित अंडर ग्रेजुएशन (यूजी) पाठ्यक्रमों में कामन यूनिविर्सटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) यूजी-2024 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने हैं। बीयू के यूटीडी में प्रवेश के लिए देशभर से सिर्फ 39 हजार विद्यार्थियों ने अपनी प्राथमिकता में बीयू को शामिल किया है। हालांकि इनमें कितने विद्यार्थी इस परीक्षा को पास कर बीयू में प्रवेश लेते हैं। यह तो सीयूईटी यूजी के परिणाम के बाद काउंसलिंग के दौरान ही पता चलेगा।

पिछले सत्र में भी सीयूईटी यूजी के माध्यम से बीयू में प्रवेश के लिए 40 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन फिर भी आधी सीटें खाली रह गई थी।

इसके बाद खाली सीटों को भरने के लिए 12वीं कक्षा के मेरिट के आधार पर काउंसलिंग आयोजित करानी पड़ी थी। हालांकि सीयूईटी यूजी-2024 का परिणाम एक-दो दिन में आने की संभावना है। सीयूईटी यूजी का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित कराया गया है।

प्रवेश की संख्या पर पड़ेगा असर

बीयू के यूटीडी पाठ्यक्रमों में हर साल सीटें खाली रह जाती है। इसके बाद भी यूटीडी में प्रवेश के लिए विद्यार्थी इंतजार नहीं करेंगे। अभी बीयू से संबद्ध कालेजों में प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर को स्कूलों का परीक्षण कर जल्द रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

सांसद-विधायकों के गोद लिए सरकारी स्कूलों की सुधरेगी दशा

सिटी चीफ भोपाल।
प्रदेश में सांसद और विधायकों द्वारा गोद लिए सरकारी स्कूलों में सरकार प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य करेगी। इसके तहत स्कूलों में निर्माण कार्य कराए जाएंगे। उनके लिए शासन की ओर से 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस राशि से उनके द्वारा प्रस्तावित स्कूल भवन का मरम्मत, बाउंड्रीवाल, जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवन के साथ पर नवीन भवन का निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय बनाने जैसे काम होंगे। शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इन निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जनप्रतिनिधियों द्वारा गोद लिए स्कूलों को प्राथमिकता में लेते हुए काम करवाने के लिए कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिले के कलेक्टर को पत्र लिखकर इन स्कूलों का परीक्षण कराकर करके प्रतिवेदन मांगा है, ताकि कार्यों की स्वीकृति दिलाई जा सके। इसमें सांसदों व विधायकों के गोद लिए गए शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल हैं। बता दें कि इस सत्र में भी मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारियों को भी स्कूल गोद लेने के लिए कहा है।

शिवराज के क्षेत्र के सात स्कूल भी शामिल

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के द्वारा दक्षिण उज्जैन विधानसभा क्षेत्र के छह सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इनमें बाउंड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष सहित अन्य निर्माण कार्य किए

जाते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के सात सरकारी स्कूलों का नाम भी सूची में शामिल हैं। होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से सीताशरन शर्मा के गोद लिए गए चार स्कूलों में निर्माण कार्य किया जाना है।

पूर्व सांसद भोपाल प्रज्ञासिंह ठाकुर द्वारा गोद लिए गए भोपाल जिले के ग्राम पंचायत खौरी में धामनिया ग्राम में तीन स्कूलों का निर्माण किया जाना है।

यहं पर शौचालय निर्माण, किचन शेड और मरम्मत कार्य किया जाना है।

अधिकारियों को लिखा है पत्र

सांसद व विधायकों ने जिन जिलों के सरकारी स्कूलों के नाम निर्माण कार्यों के लिए भेजे थे। उसके लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर परीक्षण करने के लिए कहा गया है, ताकि बजट स्वीकृत करके निर्माण कार्य कराया जा सके।

आर उमा माहेश्वरी, अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र

सम्पादकीय

देश में बाल विवाह रोकने के प्रयास काफी कम

देश प्रगति कर रहा है, लेकिन कई समाज और राज्य ऐसे हैं जहां लोगों का मानसिक विकास 18वीं सदी में ही टिका हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की शादी बचपन में ही हो गई थी। वैश्विक अनुमान के अनुसार 6.4 करोड़ लड़कियों और महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी, इनमें से एक तिहाई मामले अकेले भारत में हुए हैं।

देश प्रगति कर रहा है, लेकिन कई समाज और राज्य ऐसे हैं जहां लोगों का मानसिक विकास 18वीं सदी में ही टिका हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की शादी बचपन में ही हो गई थी। वैश्विक अनुमान के अनुसार 6.4 करोड़ लड़कियों और महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी, इनमें से एक तिहाई मामले अकेले भारत में हुए हैं। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 के अनुसार, पांच में से एक लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, जबकि 25 वर्ष पहले यह संख्या चार में से एक थी। इस सुधार ने पिछली तिमाही सदी में लगभग 68 करोड़ बाल विवाहों को रोका है।

इन प्रगतियों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दुनिया लैंगिक समानता के मामले में पीछे रह गई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और कई महिलाओं के लिए उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के मामले में स्वायत्तता की कमी जैसे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। मौजूदा गति से, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रबंधन पदों में समानता हासिल करने में 176 साल लगेंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक जीवन स्थितियों में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 169 लक्ष्यों में से केवल 17त्न ही 2030 की समयसीमा तक पूरे होने की राह पर हैं। 2015 में विश्व नेताओं द्वारा अपनाए गए इन लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करने से लेकर लैंगिक समानता प्राप्त करने तक कई तरह के मुद्दों को हल करना है। हालांकि, इनमें से लगभग आधे लक्ष्य न्यूनतम या मध्यम प्रगति दिखाते हैं, और एक तिहाई से अधिक रुके हुए हैं या पीछे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इसका निष्कर्ष सरल है। शांति सुनिश्चित करने, जलवायु परिवर्तन का सामना करने और अंतरराष्ट्रीय वित्त को बढ़ावा देने में हमारी विफलता विकास को कमजोर कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रिपोर्ट में कुछ उम्मीद की किरणें देखी हैं, लेकिन 2030 एजेंडा को पूरा करने के लिए तत्काल और त्वरित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। मूल्यांकन से पता चलता है कि केवल 17त्न लक्ष्य ही पर्याप्त प्रगति दिखा रहे हैं, जबकि 48त्न मध्यम से गंभीर विचलन प्रदर्शित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, इससे पता चलता है कि दुनिया को असफलता का दर्जा मिल रहा है।

भारत के संदर्भ में छह माह पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि देश में प्रत्येक 5 में से एक लड़की और 6 में एक लड़का शादीशुदा है। भारत में बाल विवाह को लेकर द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के सालों में चाइल्ड मैरिज की प्रथा को खत्म करने के लिए जारी प्रयासों में कमी आई है। रिसर्चर्स ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 1993 से लेकर साल 2021 तक की पांच बार के सर्वे का डेटा खंगाला। इसमें पाया कि साल 2016 से लेकर 2021 के बीच कई राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में बाल विवाह की प्रथा आम बात रही। मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्यों में बालिका विवाह (18 से कम की लड़कियों की शादी) की में इजाफा हुआ। वहीं, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर और पंजाब सहित आठ राज्यों में बालक बाल विवाह (21 से कम के लड़कों की शादी) का ग्राफ बढ़ा। इस रिसर्च में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ-साथ भारत सरकार से जुड़े लोग शामिल रहे। उनका कहना है कि भारत में चाइल्ड मैरिज में राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट आई है। 1993 में गर्ल चाइल्ड मैरिज का 49त्न था, जो 2021 में 22त्न रह गया है। वहीं, बॉयज चाइल्ड मैरिज साल 2006 में 7त्न से घटकर साल 2021 में 2त्न पर आ गई है। मगर, साल 2016 से 2021 के बीच चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास काफी कम हो गए हैं। 2006 से लेकर 2016 के दौरान चाइल्ड मैरिज में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई थी। वहीं, यूनिसेफ चाइल्ड मैरिज को लेकर मानवाधिकारों का उल्लंघन मानता है। यूनिसेफ का मानना है कि चाइल्ड मैरिज होना लड़कियों और लड़कों के विकास से समझौता करना है।

अब भारत को अपने सूचकांक तैयार करना चाहिए

वैश्विक पटल पर पश्चिमी देशों के विभिन्न संस्थानों द्वारा भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने के चलते, अब समय आ गया है कि भारत विभिन्न पैमानों पर अपनी रेटिंग तय करने के लिए अपने सूचकांक विकसित करने पर विचार करे क्योंकि वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देशों द्वारा जितने भी सूचकांक तैयार किए जा रहे हैं उसमें भारत के संदर्भ में वस्तुस्थिति का सही वर्णन नहीं किया जा रहा है।

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रेटिंग तय करने की दृष्टि से वित्तीय एवं विशिष्ट संस्थानों द्वारा सूचकांक तैयार किए जाते हैं। हाल ही के समय में इन विदेशी संस्थानों द्वारा जारी किए गए कई सूचकांकों में भारत की स्थिति को संभवत जान बूझकर गलत दशार्या गया है। इन सूचकांकों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अफ्रीका के गरीब देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में पश्चिमी देशों द्वारा जारी किए गए तीन सूचकांकों की स्थिति देखिए। सबसे पहिले उदार (लिबरल) लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग को 104 बताया गया है और भारत के ऊपर निजेर देश को बताया गया है। इसी प्रकार, आनंद (हैपीनेस) सूचकांक में भी भारत का स्थान 126वां बताया गया है जबकि पाकिस्तान को 108वां स्थान मिला है, जहां अत्यधिक मुद्र स्फीति के चलते वहां के नागरिक अत्यधिक त्रस्त हैं। एक अन्य, प्रेस की स्वतंत्रता नामक सूचकांक में भारत को 161वां स्थान मिला है जबकि इस सूचकांक में कुल मिलाकर 180 देशों को शामिल किया गया है और अफगानिस्तान को 152वां स्थान दिया गया है, अर्थात इस सर्वे के अनुसार, अफगानिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता भारत की तुलना में अच्छी पाई गई है। पश्चिमी देशों में स्थिति इन संस्थानों द्वारा इस प्रकार के सूचकांक तैयार किए जाकर पूरे विश्व को भ्रमित किए जाने का प्रयास हो रहा है।

इसी प्रकार, भारत में हाल ही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनावों पर भी पश्चिमी देशों ने कई प्रकार के सवाल खड़े करने के प्रयास किए थे। जैसे, इस भीषण गर्मी के मौसम में चुनाव क्यों कराए गए हैं, जिससे सामान्यजन वोट डालने के लिए घरों से बाहर ही नहीं निकले, ईवीएम मशीन में कोई खराबी तो नहीं है, आदि। परंतु, भारतीय मतदाताओं ने इन लोक सभा चुनावों में भारी संख्या में भाग लेकर पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया है। न ही, ईवीएम मशीन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई और न ही गर्मी का प्रभाव चुनावों पर पड़ा। हालांकि सत्ताधारी दल को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ कम स्थान जरूर प्राप्त हुए हैं परंतु देश में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सामान्यत: शांति के साथ सम्पन्न हो गए। साथ ही, विपक्षी दलों को पिछले चुनाव की तुलना में कुछ अधिक स्थान मिले हैं और उन्होंने भी चुनाव के परिणामों को स्वीकार कर लिया है। चुनाव की प्रक्रिया पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया है। इस सबके बावजूद पश्चिमी देशों ने पश्चिमी लोकतंत्र सूचकांक में वर्ष 2014 में भारत को 27वां स्थान दिया था और वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग नीचे गिराकर 41वें स्थान पर बताई गई है। जबकि वास्तव में तो इस बीच देश में लोकतंत्र अधिक मजबूत ही हुआ है, परंतु पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय लोकतंत्र को ही जैसे खतरे में बताया जा रहा है और एक तरह से भारतीय लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। दरअसल पश्चिमी देशों में कुछ शक्तियां भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं एवं ये ताकतें विभिन्न सूचकांक तैयार करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़तीं हैं। कुछ समय पूर्व एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया था। इस सूचकांक में यह बताया गया था कि भारत की तुलना में श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, एथीयोपिया, नेपाल, भूटान आदि देशों में भुखमरी की स्थिति बेहतर है। अर्थात, सर्वे में शामिल किए गए 121 देशों की सूची में श्रीलंका का स्थान 64वां, म्यांमार का 71वां, बांग्लादेश का 84वां, पाकिस्तान का 99वां, एथीयोपिया का 104वां एवं भारत का 107वां स्थान बताया गया था। जबकि पूरा विश्व जानता है कि व श्रीलंका, पाकिस्तान एवं म्यांमार जैसे देशों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी है जिसके चलते इन देशों के नागरिकों के लिए दो जून की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि, भारत कई देशों को आज खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। फिर किस प्रकार उक्त सूचकांक बनाकर वैश्विक स्तर पर जारी किए जा रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि भारत की आर्थिक तरक्की को विश्व के कई देश अब सहन नहीं कर पा रहे हैं एवं भारत के बारे में इस प्रकार के सूचकांक जारी कर भारत की साख को वैश्विक स्तर पर प्रभावित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

युद्ध की विभीषिका झेल रहे एथीयोपिया में नागरिक अपनी भूख मिटाने के लिए घास जैसे भारी पदार्थों को खाकर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच जीवन यापन करने वाले नागरिकों को भुखमरी के मामले में भारत के नागरिकों से बेहतर स्थिति में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इन लोगों को खाने पीने सम्बंधी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। फिर भी भारत के नागरिकों को भुखमरी सूचकांक में ईथीयोपिया के नागरिकों की तुलना में इतना नीचे बताया गया है। अब कौन इस प्रकार के सूचकांकों पर विश्वास करेगा। यह भी बताया जा रहा है कि इस सूचकांक को आंकने के लिए भारत के 140 करोड़ नागरिकों में से केवल 3000 नागरिकों को ही इस सर्वे में शामिल किया गया था। इस प्रकार सर्वे का सैम्पल बनाते समय भारत जैसे विशाल देश के लिए अपर्याप्त संख्या का उपयोग किया गया है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की सावरेन क्रेडिट रेटिंग पर कार्य कर रही संस्था स्टैंडर्ड एंड पूअर ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था का आंकलन करते हुए भारत के संबंध में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक किया है एवं कहा है कि वह भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के उद्देश्य से भारत के आर्थिक विकास सम्बंधी विभिन्न पैमानों का, आधारभूत ढांचे को विकसित करने एवं भारत के राजकोषीय घाटे को कम करने से सम्बंधित आंकड़ों एवं प्रयासों का गम्भीरता से लगातार अध्ययन एवं विश्लेषण कर रहा है। आगे आने वाले दो वर्षों के दौरान यदि उक्त तीनों क्षेत्रों में लगातार सुधार दिखाई देता है तो भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया जा सकता है। वर्तमान में भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग बीबीबी- है, जो निवेश के लिए सबसे कम रेटिंग की श्रेणी में गिनी जाती है।

किसी भी देश की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को यदि अपग्रेड किया जाता है तो इससे उस देश में विदेशी निवेश बढ़ने लगते हैं क्योंकि निवेशकों का इन देशों में पूंजी निवेश तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जाता है। साथ ही, अच्छी सावरेन क्रेडिट रेटिंग प्राप्त देशों की कम्पनियों को अन्य देशों में पूंजी उगाहना न केवल आसान होता है बल्कि इस प्रकार लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की राशि भी कम देनी होती है। किसी भी देश की जितनी अच्छी सावरेन क्रेडिट रेटिंग होती है उस देश की कम्पनियों को कम से कम ब्याज दरों पर ऋण उगाहने में आसानी होती है। परंतु, भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के लिए स्टैंडर्ड एंड पूअर को दो वर्षों का समय क्यों चाहिए? जब इन समस्त क्षेत्रों में लगातार सुधार होते साफ दिख रहा है।

साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई विदेशी संस्थान (विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आदि) आगे आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर बहुत उत्साहित हैं एवं आर्थिक प्रगति के साथ साथ राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना करते रहते हैं। फिर भी, स्टैंडर्ड एंड पूअर को भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने के लिय दो वर्षों का अतिरिक्त समय चाहिए।

वैश्विक पटल पर पश्चिमी देशों के विभिन्न संस्थानों द्वारा भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने के चलते, अब समय आ गया है कि भारत विभिन्न पैमानों पर अपनी रेटिंग तय करने के लिए अपने सूचकांक विकसित करने पर विचार करे क्योंकि वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देशों द्वारा जितने भी सूचकांक तैयार किए जा रहे हैं उसमें भारत के संदर्भ में वस्तुस्थिति का सही वर्णन नहीं किया जा रहा है।

देश की सुरक्षा और शांति ही राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का लक्ष्य : इंद्रेश कुमार

दुनिया को दिशा देगा हमारा देश, बनेगा दिव्य भारत = गोलोक बिहारी राय

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की तीन दिनी वार्षिक आमसभा संपन्न भोपाल, विकसित भारत का लक्ष्य केवल सुख सुविधाएं और भौतिक विकास नहीं है, बल्कि दुनिया को दिशा देना हमारा विचार है। विकसित और दिव्य भारत के निर्माण के लिए हमें मिलकर लगातार प्रयास करने होंगे। यह बातें प्रसिद्ध चिंतक और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच (फैन्स) के राष्ट्रीय महामंत्री गोलोक बिहारी राय ने कहीं। इंद्रेश कुमार बोले- मंच के प्रति लोगों की भ्रांतियां करनी होगी दूर कई लोगों को लगता है कि हमारा संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच हिंसक विचार रखता है, समाज में हमारे प्रति कई गलतफमियां फैलाई गई हैं। इसलिए अपने कार्यक्रमों में स्थानीय नागरिकों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बुलाएं ताकि उन्हें पता चल सकेगा कि हमारा लक्ष्य राष्ट्र की सुरक्षा और शांति है। हमारी सभी ईकाईयों को समाज में फैली भ्रांतियां दूर करनी होंगी। यह बातें राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच (फैन्स) के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने रविवार को पचमढ़ी में कहीं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि हम आतंकवादियों को मारकर आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते। हमें वह कारण समझने होंगे कि लोग आतंकवादी क्यों बन रहे हैं? और उस कारण को ही समाप्त करना होगा। हमें समाज को जागरुक करना होगा कि हमारा समाज सेना, सरकार और पुलिस का सहयोग करे। हमें सिर्फ उपदेशक नहीं बनना है, हमें खुद अपने आचरण में भी यह बातें उतारनी हैं।

घुसपैठ में पशुओं की आवाज का उपयोग

इंद्रेश कुमार ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोकने में वहां के स्थानीय नागरिक काफी मदद कर सकते हैं। घुसपैठ से पहले आतंकवादी पशु—पक्षियों की आवाज निकालकर संदेश प्रसारित करते हैं। कभी बिल्ली, कभी कुत्ते के भोंकने, तो कभी गीदड़ की आवाज निकालकर आतंकवादियों को सचेत करते हैं।

भारत को आदर्श महाशक्ति बनना है = अवेध कुमार

विचारक अवधेश कुमार ने कहा कि कई वर्षों से भारत के नागरिकों के संस्कारों में सेवा का भाव रहा है। भारत में त्याग की प्रवृत्ति सुखद है। आज का भारत दुनिया को दिशा दे रहा है। भारत को सिर्फ सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति नहीं बनना है, भारत को आदर्श महाशक्ति बनना है।

कार्यकारिणी और ईकाईयों की घोषणा गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 30 जून को राष्ट्रीय जागरण मंच की वार्षिक आमसभा की बैठक संपन्न हो गई। 28 जून से शुरू हुई इस तीन दिवसीय बैठक के अंतिम दिन राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के कार्यकारिणी की घोषणा हुई। इसके साथ ही विभिन्न चैप्टर की घोषणा भी की गई और वर्ष भर चलने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा हुई।

लोकतंत्र पर हावी हो रहा अलगाववाद

चार जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए मतदाताओं के जनादेश ने देश-दुनिया के सियासी पंडितों के अनुमान को ध्वस्त करके मुल्क की सियासत को हैरत में डाल दिया था। चुनावी समर में सियासी दुर्ग फतह करने के लिए कई तरह के लोकलुभावन वादों की बिसात बिछाई जाती है। ज्यादातर सियासी जमातों की सियासत जाति-मजहब, क्षेत्रवाद व वंशवाद की सदारत करती है। चुनावों के दौरान लोगों को मुफ्तखोरी के प्रलोभन देना सियासत की फितरत बन चुका है। मगर जागरूक व सतर्क मतदाता शिक्षित व साफ छवि वाले जनप्रतिनिधि को लोकतंत्र का भाग्य विधाता चुनने की कोशिश करते हैं, ताकि लोकतंत्र की संस्थाओं में आम लोगों के हितों की पैरवी हो तथा सत्तापक्ष द्वारा निर्धारित की गई नीतियों पर सकारात्मक बहस हो सके। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सियासत का मिजाज बदल रहा है। जब जम्हूरियत के निजाम में आवाम कुछ बातों को अपनी जुबान से बयान नहीं कर पाती तो खामोशी से अपने वोट के जरिये सियासी रहनुमां का चुनाव करके अपने जज्बातों का इजहार किया जाता है। मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्षी दलों ने महंगाई व बेरोजगारी पर जोरदार ताकीद पेश करके देश के आईन को बचाने का हवाला भी दिया था। मगर कुछ सीटों पर लोगों का जनादेश हैरतअंगेज करने वाला रहा है।

मतदाताओं ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को देश की संसद में भेजने का फरमान जारी कर दिया है जो अलगाववाद की खुलेआम हिमायत करते हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेलों में बंद हैं। भारत में रहकर अपने ही मुल्क को खंडित करने वाली मनोग्रंथी से पीड़ित होकर टेरर फंडिग व आतंकी गतिविधियों के मामले में सलाखों के पीछे हैं। विडम्बना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके तथा गैंगेस्टर व आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में जेलों में बंद माफियाओं को देश का संविधान चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या चरमपंथ व अलगाववाद की हिमायत करने वाले प्रतिनिधि संविधान के प्रति आस्था व विश्वास रखते हैं, संवैधानिक सिद्धांतों को तसलीम करते हैं। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके प्रत्याशी जेलों में बैठकर चुनाव जीत जाएं तथा मर्डर व आर्म्स एक्ट जैसी संगीन वारदातों में मुल्लविस सियासी रहनुमाओं को मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजेंगे तो जम्हूरी निजाम के साथ मुल्क के आईन पर भी सवाल उठेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति इस कारकर्दगी को मतदाताओं की नाराजगी समझें या मतदान के प्रति जागरूकता का अभाव। लेकिन मतदाताओं ने कट्टरवाद के हिमायती कुछ सियासी रहनुमाओं को प्रतिनिधि चुनकर मुल्क की सियासत को जो पैगाम दिया है, उस नजरिए को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश में ऐसे कई सियासी रहनुमां हैं जिनके नाम के साथ माफिया, डॉन व बाहुबली जैसे लफ्ज जुड़े हैं। सलाखों के पीछे बैठकर चुनाव लडकर अपने सियासी रुतबे की नुमाईश करना भी देश में एक फैशन बन चुका है। सियासत की यह कारगुजारी सोचने पर मजबूर करती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के लिए राजा-महाराजाओं ने अपनी रियासतों का हिंदोस्तान में इलहाक करके जिस प्रजातंत्र की कल्पना की थी, क्या वो लोकतंत्र कायम हुआ। यदि अलगाववाद व कट्टरपंथ की पैरवी करने वाली जहनियत भी जम्हूरियत की सबसे बड़ी पंचायत में तशरीफ ले जाएगी तो ऐसी विचारधाराओं का संगम राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा बनेगा। कई जनप्रतिनिधि फरमाते हैं कि सियासत समाज के कल्याण व आवाम की खिदमत का माध्यम है, लेकिन सियासतदानों की कार्यशैली दर्शाती है कि सियासत का मकसद केवल सत्ता की दहलीज पर पहुंचने के लिए ही रह गया है। जम्हूरियत की बुलंदी पर पहुंचने की लालसा हर जनप्रतिनिधि के जहन में कायम है। ज्यादातर सियासी रहनुमाओं पर सियासी रसूख की हनक, अक्सरियत का खुमार व इक्तदार का गुमान हावी रहता है। धनबल, बाहुबल, मौकापरस्ती व अलगाववाद जैसी विचारधाराओं के मिलन से सियासत विवशता का खेल बन चुकी है। चुनाव विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डैमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) के अनुसार नब्बे प्रतिशत से अधिक सांसद करोड़पति की फेहरिस्त में शामिल हैं। जाहिर है हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के वारिस प्रतिनिधि गुरबत से जूझ रही आवाम की मजबूरी नहीं समझ सकते।

बेरोजगारी की गर्दिश में फंसे युवा वर्ग के हिज्र का दर्द महसूस नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार से लेकर बेहद संगीन जुर्म तक ऐसा कोई अपराध नहीं जिसके तार सियासत से न जुड़े हों। सियासतदानों की कारगुजारियों से निर्वाचन आयोग व प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां भी परेशान हो चुकी हैं, मगर माफिया, बाहुबली व अलगाववादी जैसे सियासी एजाज हासिल होने के बावजूद सियासी रहनुमाओं के प्रति आवाम का नजरिया अदब का ही रहता है। इसीलिए सियासत अपराध से मुक्त नहीं हो रही। तोहमत, फरेब व दलबदल से लबरेज सियासत सियासी रहनुमाओं के लिए एक इबादत का विषय बन चुकी है। अलगाववाद की असबियत तथा आपराधिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले प्रतिनिधि यदि देश के नीति निमार्ता बनकर संसद में मौजूद होंगे, तो रक्षा क्षेत्र जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासी नजर-ए-करम की उम्मीद नहीं की जा सकती। चूंकि हिंदोस्तान की सलामती के खिलाफ मंसूबे बनाने वाले बैरूने मुल्क भी अलगाववादियों की पुरजोर हिमायत करते हैं, यदि लोकतंत्र के मुख्य स्तम्भ विधायिका व कार्यपालिका भी अलगाववाद व चरमपंथ की गिरफ्त में आ जाएंगे, तो सबसे बेहतर शासन व्यवस्था प्रजातंत्र में अदब, एहतराम व सादगी जैसे गुणों की गुंजाइश नहीं रहेगी। बहरहाल जम्हूरियत की सबसे बड़ी पंचायत में चरमपंथ व अलगाववाद की रफाकत लोकतंत्र के लिए नदामत का सबब बनेगी। अत: संवैधानिक लोकतंत्र में अलगाववादी मानसिकता मंजूर नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र को महफूज रखने के लिए आपराधिक छवि वाले सियासी रहनुमाओं के प्रति हमदर्दी से परहेज करना होगा। उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना होगा।

परिवहन क्षेत्र में सुशासन का महत्वपूर्ण कदम : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ग्वालियर

शिकायतों पर होगी सख्त कार्रवाई

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए विस्तृत दिशा-निर्देश

प्रदेश में गुजरात पैटर्न पर लागू होगी नई चेक पोस्ट व्यवस्था

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती हैं वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। प्रदेश में चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था गुजरात पैटर्न पर लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को भोपाल में मुख्यमंत्री निवासी स्थित समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को परिवहन विभाग की नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किस प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवहन विभाग को नई व्यवस्था लागू करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा प्रदेश में अब सीमावर्ती जिलों में नई व्यवस्था के तहत उड़न दस्ते कार्य करेंगे। बाहरी वाहनों के संचालकों को कोई समस्या नहीं आएगी। नई पारदर्शी व्यवस्था सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि परिवहन विभाग द्वारा महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करने के लिए शिविर लगाए जाएं। यात्री बसों के संचालन में निर्धारित स्थान से बस चलाने के नियम का पालन किया जाए। समय सारणी का पालन किया जाए। स्कूल की बसों की चेकिंग भी की जाए। ग्रामीण परिवहन सेवा को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाए। भोपाल में वीडियो कांफ्रेंस कक्ष में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव परिवहन श्री एस. एन. मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव जनसम्पर्क एवं विमानन श्री संदीप यादव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ग्वालियर में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री, पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद सक्सेना, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री हर्ष सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार, वन मण्डलाधिकारी श्री अंकित पाण्डेय एवं अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। गुजरात पैटर्न की विशेषताएं और मध्यप्रदेश में इसकी शुरूआत परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण में वृद्धि और व्यवस्थित कार्य प्रणाली लागू करने की पहल करते हुए प्रदेश में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। शिकायतों को समाप्त किया जा सकेगा। वाहन चालकों और संचालकों की दिक्कतें दूर होंगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत अहम निर्णय किया गया है। परिवहन क्षेत्र में चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट रहेंगे। अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़नदस्ते कार्य करेंगे। कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे। प्रदेश में 211 होमगार्ड के लिए आवश्यक व्यवस्था हुई है जो सेवाएं देंगे। उन्हें नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आवंटित जिलों में पदस्थ किया गया है। होमगार्ड जवान क्रमशः अपनी डयूटी करेंगे। प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा। परिवहन नाकों के स्थान पर मोबाइल टीम कार्य करेगी। चेक पॉइंट पर पदस्थ अमला समयावधि में बदलेगा। प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसे जिले चयनित किए गए हैं जो सीमावर्ती हैं।

पौधों की सुरक्षा के पूरे प्रबंध करके वृक्षारोपण कराएं-

उड़न दस्ते गठित कर वाहनों की सघन जांच कराएं - मुख्यमंत्री

सीधी

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। अभियान के दौरान 3885 नए जल स्रोतों का विकास किया गया है इसके साथ-साथ 21577 जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया है। इनमें 5677 बावड़ी तथा 13000 से अधिक तालाबों में साफ सफाई और जल संरक्षण का कार्य शामिल है। जल संवर्धन के जो कार्य जारी हैं उन्हें अधिक बरसात होने से पहले पूरा कर लें। जल संरक्षण और संवर्धन का अभियान एक दिन का नहीं है इसके लिए हमें सतत प्रयास करने होंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान में आम जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। जन सहयोग से इस अभियान को हम लगातार जारी रखेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वृक्षारोपण का आह्वान किया है। हर जिले में पूरी कार्य योजना बनाकर पौधों की सुरक्षा और देखभाल की पूरी व्यवस्था करते हुए वृक्षारोपण कराएं। हर जिले में स्मृति वनों का निर्माण कर के उसमें आम जनता से उनके पूर्वजों की स्मृति में पौधे लगाएं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य है। हर परिवार कम से कम एक पौधा अवश्य रोपित करें और उसकी देखभाल करें। वन विभाग भी खाली पड़ी वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में 1 जुलाई से तीन नए कानून लागू किया जा रहे हैं। इनमें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर नए कानून का निर्माण किया गया है। पुलिस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों को नए कानून के संबंध में प्रभावी प्रशिक्षण दें ।आम जनता को नए कानून तथा उनकी धाराओं की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग के सभी चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं। अब जिले में प्रवेश करने के बाद वाहनों की जांच की जाएगी। इसके लिए 211 होमगार्ड परिवहन विभाग को प्रदान कर दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में उड़न दस्ते गठित करके वाहनों की जांच कराएं। ओवरलोड वाहनों तथा अन्य अनियमिता करने पर कड़ी कार्रवाई करें। प्रदेश भर में स्कूल शुरू हो गए हैं। सभी कलेक्टर स्कूल बसों की सघन जांच कराएं। बसों में सुरक्षा उपायों तथा किसी भी तरह की कमी होने पर कड़ी कार्रवाई करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वन विभाग 82806 हेक्टेयर में 5 करोड़ 39 लाख पौधे रोपित करेगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में प्रारंभिक तैयारी कर ली गई है। वृक्षारोपण के लिए 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इंदौर में 45 लाख पौधे रोपित करने की तैयारी कर दी गई है। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एनआईसी केंद्र सीधी से कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉ रविन्द्र वर्मा, वनमंडलाधिकारी श्री क्षितिज कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राहुल धोटे, अपर कलेक्टर श्री राजेश शाही, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास श्री नीलेश शर्मा, कुसमी श्री एसपी मिश्रा, मझौली आर पी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी एवं संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

जिला प्रशासन शिक्षा की गुणवत्ता के लिए संकल्पित

अब नियमित होगा शालाओं का निरीक्षण, लापरवाह शिक्षकों पर होगी कार्यवाही

उमरिया उमरिया - नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के अनेकों प्रयास सत्र प्रारंभ से ही शुरू कर दिए हैं। शालाओं में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के साथ ही विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब स्कूलों में जिला तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों व्दारा औचक निरीक्षण करने के साथ ही, बीईओ, बीआर सी, बीएसी सहित अन्य प्रशासनिक अमले की जवावदेही तय की जायेगी। इतना ही नहीं मासिक टेस्ट, समय पर पाठ्यक्रम का अनुसरण, स्कूलों में शैक्षणिक वातावरण तैयार करने हेतु किये गए प्रयासों, साफ सफाई, शौचालयों के उपयोग तथा सफाई, पेयजल की व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन, पाठ्य पुस्तकों के वितरण, गणवेश, छात्र व्रत्ति , शिष्यवृत्ति के वितरण, बाल सभा, पालक शिक्षक संघ की बैठक, अभिभावक भेंट तथा निरीक्षण में पायी गयी कमियों को दूर करने हेतु किये गये प्रयासों की भी मानीटरिंग की जायेगी।

राजगढ़ पाडल्या माताजी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास एवं रोजगार विभाग श्री गौतम टेटवाल ने श्रवण किया। इस अवसर पर सांसद श्री रोडमल नागर,जनप्रतिनिधि,ग्रामीणजन भी मौजूद रहें।

डिंडोरी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत श्री अन्न के उत्पादन, रकबे और संवर्धित उत्पादों के मूल्य को बढ़ाने हेतु 29 जून 2024 को जिला बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा श्री अन्न कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिसमें डिंडोरी द्वारा भी जिला प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में श्री अन्न की प्रदर्शनी लगाई गई। जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। साथ ही डिंडोरी जिले के महिला समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न व्यंजनों का स्वलापहार भी किया गया। विदित है कि हमारे महिला समूहों द्वारा श्री अन्न के बिस्कुट, नमकीन , लड्डू, ब्रेड, केक, कप केक, सेवई, पापड़, खीर, पुलाव इत्यादि व्यंजन बनाए जाते है।

मानसून के चलते जिले के नदी, नालों से रेत उत्खनन प्रतिबंधित - कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

बैतूल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आगामी चार माह तक नदी, नालों से रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। खनिज विभाग के उप संचालक मनीष पालेवार ने बताया कि मानसून के कारण जिले की समस्त रेत खदानों, नदियों एवं नालों से रेत उत्खनन पर 30 जून 2024 की मध्यरात्रि से 01 अक्टूबर 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

डी.ई.एम.सी की बैठक सम्पन्न

मन्दसौर डी.ई.एम.सी की बैठक जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई । बैठक के दौरान व्यय प्रेक्षक श्री एस.एस. दास, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव, व्यय नोडल अधिकारी एवं सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम एवं समस्त सहायक व्यय प्रेक्षक के साथ-साथ अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता, सभी विधानसभा क्षेत्र के व्यय लेखा दल उपस्थित थे । बैठक में समिति के द्वारा सभी उपस्थितगणों से चर्चा की गई एवं लेखों का परीक्षण समिति के मार्गदर्शन में सम्पादित किया गया।

सतना मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री निवास समत्व से जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान किये गए कार्य, प्रस्तावित पौधारोपण अभियान की तैयारी और अन्तर्राज्यीय परिवहन चेक पोस्ट की नई पारदर्शी व्यवस्था पर जिलों के कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक सहित जिलाधिकारियों से वीसी के माध्यम से चर्चा की गई। सतना के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत सुश्री संजना जैन, नगर निगम आयुक्त श्री शेर सिंह मीना सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आम जन तक पहुँचाएं नए स्वरूप में लागू किए गए कानून की जानकारियां: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

वीडियो कांफ्रेंस द्वारा सभी जिलों को दिए गए निर्देश

नर्मदापुरम

मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi की पहल से देश में गुलामी की निशानियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न कार्य हो रहे हैं। इस क्रम में एक जुलाई से देश में अनेक कानून नये स्वरूप में लागू होंगे। दंड के स्थान पर न्याय का महत्व बढ़ें एवं भारतीय नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हो सके, इस चिंतन से तीन विधेयक निरस्त कर नए दंडनीय विधेयक लाए गए हैं। आम जन तक इनकी जानकारी पहुँचाने के सभी प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज वीडियों कान्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे ऐसे विधेयक एवं अधिनियम में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

एक पेड़ अपनी मां के नाम लगा सेल्फी लेवें मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ अपनी मां के नाम का अभियान भी सभी कलेक्टर्स अपने जिले में चलाऐं इस अभियान के तहत जिनकी मां जिवित है वे अपनी मां के साथ एक पौधा लगाकर सेल्फी ले एवं जिनकी मां इस दुनिया में नहीं है वे पौधा लगाकर

अपनी मां की फोटो के साथ सेल्फी लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौध रोपण अभियान के तहत प्रदेश में साढ़े पांच करोड़ पौधे लगाये जाऐंगे। सभी पौधे जीवित रहे एवे उनकी सुरक्षा होती रहे। हम जो पौधा लगाए वो सरवाइव करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौध रोपण अभियान में कलेक्टर लीड करें।

जलसंवर्धन अभियान निरंतर चलता रहे मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतिम दिन 30 जून को समापन कार्यक्रम के संबंध में सभी कलेक्टर्स से कहा कि जल संवर्धन का अभियान वर्ष भर चलता रहे। कुऐ, बावड़ी, नदी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य कभी न रुके उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक दीर्घकालिक योजना बनाई जाए कि कैसे हम जल एवं रोजगार को जोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। वहां मछली पालन कर लोगो को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

एक सप्ताह में बसों की चेकिंग की जाए चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती हैं वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। उन्होंने एक सप्ताह में बसों की चैकिंग करनें एवं उडनदस्ता दल को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर्स यह सुनिश्चित करेगे कि सभी बसे बस स्टेंड से ही चले एवं वापस बस स्टैंड ही आऐ। समय सारणी का पालन हो। कॉलेजो में शिविर लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाऐं

नर्मदापुरम के एनआईसी कक्ष में संभागायुक्त श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, आईजी इरशाद वली, अपर आयुक्त श्री आरपी सिंह, कलेक्टर सोनिया मीना, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सोजान सिंह रावत, अपर कलेक्टर श्री डी के सिंह, उपायुक्त राजस्व श्री गणेश जैसवाल, डीएफओ श्री मयंक गुर्जर, संयुक्त उपायुक्त श्री जीपी दोहर, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक आशुतोष मिश्रा एवं संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

द डायरी ऑफ बेस्ट बंगाल फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पहुंचे चित्रकूट

जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से की मुलाकात

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ चित्रकूट/सतना, चित्रकूट पहुंचे द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी के डायरेक्टर सनोज मिश्रा द्वारा पद्म विभूषण जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया गया। साथ ही सनोज मिश्रा द्वारा द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी की लॉन्चिंग का शुभ मुहूर्त भी पद्म विभूषण श्री रामभद्राचार्य जी महाराज से पूछ कर अगस्त माह में मूवी लॉन्च करने की तारीख निश्चित कर ली गई है।गौर तलब है कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी काफी विवादों से घिरी रही है, जिसको लेकर के बंगाल की सरकार द्वारा मूवी के डायरेक्टर सनोज मिश्रा के ऊपर 26 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। फिल्म को लेकर बंगाल सरकार का कहना था कि इस फिल्म माध्यम से बंगाल की छवि खराब की जा रही है। इसलिए फिल्म को तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। दूसरी तरफ फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा का कहना था कि संदेश खली में

क्या हुआ,चुनावों के समय सबसे अधिक लोग बंगाल में ही क्यों मरते हैं, सबसे अधिक बम गोला बंदूक आखिरकार बंगाल में क्यों चलते हैं।और जब सच्ची घटनाओं को लेकर कोई फिल्म बनाता है,तब बंगाल सरकार कहती है कि बंगाल की छबि खराब हो रही है।सनोज मिश्रा ने कहा कि बंगाल की छबि तो खुद वहां की सरकार के द्वारा खराब करके रखी गई है,मैं तो केवल बंगाल की सरकार को आईना दिखा रहा हूं। अब आपकी सरकार की शक्ल ही बदसूरत है तो उसमे मैं क्या कर सकता हूं। बंगाल सरकार के भारी विरोध के बावजूद सेंसर बोर्ड द्वारा द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी को ग्रीन सिग्नल दिया गया है।जिसके बाद अब द डायरी ऑफ़ वेस्ट बंगाल मूवी को सनोज मिश्रा जल्द ही अगस्त माह में रिलीज करने वाले हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सनोज मिश्रा ने कहा कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी, बंगाल में रह रहे हिंदुओं के साथ की जा रही प्रताड़ना तथा हिंदुओं के साथ हो रहे वास्तविक उत्पीड़न के वास्तविक तथ्यों पर आधारित फिल्म है।इसलिए इस फिल्म को सभी देश वासियों को देखना चाहिए।

सभी आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकासखण्डों में 01 जुलाई से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है संपूर्ण अभियान

04 से 06 जुलाई के बीच इस अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में होगा

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2024 से देश के सभी आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकासखण्डों में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम संपूर्ण अभियान है। आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकासखंड या एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एसपिरेशनल ब्लॉक उसे कहते हैं, जिसे भारत सरकार ने आईडेंटिफाई किया है, जहां किसी समय में अधिक पिछड़ापन था और उसको आईडेंटिफाई करने के बाद, वहां पर अलग-अलग विकास के सूचकांको पर काम हो रहा है, ताकि यह जो जिले हैं यह विकास की श्रेणी में अग्रणी बन सके और हमारे जिले की बात की जाए तो दमोह आकांक्षी जिला भी है और तेंदूखेड़ा ब्लॉक आकांक्षी विकासखंड की श्रेणी में आता है। यह बात कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आज संपूर्ण अभियान के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा सहित, सीईओ जनपद, एनजीओ और

सामाजिक संस्थायें मौजूद थे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग एवं आजीविका मिशन के अधिकारी भारत सरकार द्वारा 6 इंडीकेटर्स शत-प्रतिशत पूर्ण किये जाने कार्य योजना तैयार की गई।

कलेक्टर ने कहा नीति आयोग भारत सरकार ने एक अभियान लिया है 01 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक जिसका नाम संपूर्ण अभियान रखा गया है, जैसा की शब्द से समझ में आता है, संपूर्ण यानी पूरा।

इन्होंने 6 अलग-अलग इंडिकेटर दिए हैं और यह अपेक्षा की है कि शत-प्रतिशत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाये। उन्होंने कहा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पहले त्रीमास में जो ए.एन.सी. की जांचे है, जो स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर होती है, वह शत-प्रतिशत महिलाओं की हो जाए। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इनकी जांच हो जाए, इसके अलावा स्व-सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज मिल जाए, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को पूरा पोषण आहार आंगनबाड़ियों के माध्यम से मिल जाए जिसको टेक होम राशन कहा जाता हैं। अलग-अलग लक्ष्य है जिन लक्ष्यों को इस अभियान के अंतर्गत पूरा करना है।

स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ पौधरोपण के संबंध में अहम् बैठक संपन्न

सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा विशेष रूप से बैठक में मौजूद रहें

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, वृक्षारोपण अभियान के संबंध में आज कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा इस अभियान में महिलाओं और बच्चों को शामिल किया जाए, प्लांटेशन के काम में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए, साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था समुचित की जाए, लक्ष्य नहीं पौधे सुरक्षित रहें यह सुनिश्चित करना है। आयोजित बैठक में सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे।

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम से लगाया जाए। उन्होंने बताया यह सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोग आए और मां के नाम से मां की स्मृति में पौधा जरूर लगाए, स्थान की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अर्पित

वर्मा ने कहा इस दौरान सभी जनपद पंचायत द्वारा शीड बॉल के साथ ही पौधारोपण का कार्य किया जाना है। बैठक में जनपद और नगर पालिका की समीक्षा की गई। दमोह नगर पालिका द्वारा बताया गया कि इस दौरान उन्हें एक लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य मिला है, इसी प्रकार सभी नगरी निकायों को 15-15 हजार वृक्षारोपण का लक्ष्य मिला है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 08 लाख 21 हजार पौधे वन विभाग द्वारा रोपित किये जा रहे हैं। 52 सेंटर में रोपण किया जाना है, पूरे जुलाई माह यह रोपण किया जाएगा। बटियागढ़ जनपद पंचायत के सीईओ ने बताया कि 29800 पौधे उनके द्वारा रोपित करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार सभी सीईओ ने अपनी जानकारी दी। बैठक में मौजूद स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपनी-अपनी बातें, विचार और सुझाव भी रखें।

जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजित

श्री जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ

रणधीर चंदेल । सिटी चीफ गुना, गुना जिला रोलर स्केटिंग संघ गुना द्वारा आयोजित 6वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता 2024 का जेल रोड गुना से आरंभ किया गया। जिसका विधिवत शुभारंभ मुख्यातिथि भाजपा जिला मिडिया प्रभारी एवं जिला रोलर स्केटिंग संघ गुना के अध्यक्ष विकास जैन नखराली द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का आरंभ कराया साथ ही श्री जैन ने जिले भर से आए स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए उन्हे बधाई शुभकामनाएं प्रेषित कर उनके उज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जिला रोलर स्केटिंग संघ सचिव एवं स्केटिंग कोच आशा सिंह ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों जिसमें 100 मीटर एवं 200 मीटर की प्रतियोगिता को संपन्न कराया। उक्त प्रतियोगिता के निर्णायक अजय रघुवंशी एवं डॉ ह्रदेश गुप्ता द्वारा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय खिलाड़ियों को चयनित अपना निर्णय दिया। सभी चयनित खिलाड़ियों को पुरुस्कार वितरण किया जायेगा।

नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी कर रहे है अपनी जिंदगी बर्बाद

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ सतना, भारत युवाओं का देश है, और दुनिया की सबसे तेजी से उभरती शक्ति है लेकिन एक तरह से शक्ति का सबसे अधिक दुरुपयोग करने वाला देश भी। देश की आजादी के वक्त भी इतनी अराजकता नहीं रही होगी जितनी 21वीं शदी के भारत में दिखाई देती है। विगत दस वर्षों में देश के युवा नशे की ओर अधिक अग्रसर हो गए है, एक समय ऐसा भी था जब भारतीय समाज मे नैतिकता अपने चरम पर थी, पर समय परिवर्तन और आधुनिक तकनीकों का गलत उपयोग करने से इसका लगातार पतन होता चला गया। समाज में संयुक्त परिवार की जगह अब एकल परिवार ने ले ली है जिसके कारण बच्चे जो दादा, दादी से नैतिकता के पाठ सीखते थे अब उस नैतिकता का पाठ पढ़ने के लिए घरों में ना दादी है और ना दादा! जो बच्चों को सही और गलत का पाठ पढ़ा सकें। जीवन में व्यस्तताओं के चलते माता- पिता प्राय: बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते है इसी कारण आज युवा नैतिकता के पाठ को भी भूलता जा रहा है। देश के किसी भी शहर, कस्बे, गाँव को अगर देखा जाए तो अधिकांशत: युवा किसी ना किसी नशे की लत में गिरफ्त मिल जायेगें। आसपास के क्षेत्र मे कई बार सड़क पर अथवा सड़क के किनारे युवा नशे का सेवन करते देखे जा सकते है। क्या वास्तव में देश की युवा शक्ति देश के विकास मे सहायक हो सकती है? क्या इस स्थिति के लिए देश के महान नायकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी? इस हेतु स्वरचित एक कविता की चार लाइन यथार्थ होती है- देश है आजाद लेकिन जश्ने-आजादी भी चाहिए, हो रहा क्या देश में यह

बात लिखनी चाहिए। भूल बैठे हो अगर इतिहास अपना साथियों, फिर सभी एक साथ हो इक आस दिखनी चाहिए।। अगर आकड़ों के मायाजाल पर ध्यान ना दिया जाए और यथार्थ के तथ्यों पर ध्यान दिया जाए तो देश में युवाओं के हालात बहुत अच्छे नहीं है, यह कहना उचित ही होगा कि आज देश का युवा जिस पर देश का भविष्य निर्भर है वह अब स्वयं का भविष्य भी अंधकारमय करता जा रहा है, आज का युवा न केवल बेबस और लाचार दिखाई पड़ रहा है वरन वह अपने पथ से भटकता भी नजर आ रहा है। युवा शब्द से तात्पर्य सिर्फ पुरुष वर्ग से नहीं है अपितु इसमें समान रूप से महिलाएं भी सम्मिलित है। समाज में अलग-अलग तरह के नशे में अब यह युवा अपनी व देश की शक्ति दोनों का विदोहन करते जा रहे है। नशीली दवाओं एवं नशीले द्रव्य पदार्थों की पकड़ अब छोटे शहरों, कस्बों व गांवों तक पहुँच चुकी है। शराब,तंबाकू, गुटखा, चरस, गाँजा,अफीम, एवं विभिन्न प्रकार के नशे की गोलियां अब न केवल युवा अपितु छोटे बच्चों मे भी प्रचारित हो चुकी है और वे इनका दोहन भी कर रहे है, समाज का युवा इस हद तक नशे कि गिरफ्त मे है कि वह खासी की दवाई तक का उपयोग नशे के रूप में करता है, हमारे समाज में यह भी देखने को मिल रहा है कि शहरों मे निवासरत गरीब तबके के नैनीहाल अब वाहनों के पंचर बनाने मे उपयोग होने वाले पदार्थ का उपयोग नशे के रूप मे कर रहे है। आज की इस युवा पीढ़ी में नशे को कूल दिखने से जोड़ा जाता है यदि कोई लड़का नशा करता है तो वह इसका शर्म से नहीं अपितु बड़े ही गर्व के साथ बखान करता है, और इसी का दुष्परिणाम है कि नशे का प्रसार इतना व्यापक हो चुका है कि युवा प्राय: बाल्यावस्था से ही इसकी चपेट मे आ जाता है, अब छठवी कक्षा मे पढ़ रहा बालक भी एक बार नशा करना चाहता है, सामान्यत: यह कुछ नया जानने की इच्छा के कारण होता है तो कई बार वे टेलीविजन, मोबाइल अथवा अपने घर के बड़ों मे ही इसका प्रयोग करते देखता है और सामान्यत: वह इसका एक बार शौकिया रूप से चोरी छिपे प्रयोग करते है और फिर धीरे-धीरे उन्हे इसकी आदत हो जाती है। समाज में नशे का प्रसार इतना ज्यादा हो चुका है कि बच्चे किशोरावस्था तक की उम्र मे नशे का व्यसन नियमित रूप से करने लगते है। नशे की लत के कारण कई प्रकार की बीमारियां होती है जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े का खराब होना, अब तो विभिन्न प्रकार की दवाईयों का सेवन करने से युवा वर्ग मे मिर्गी जैसी बीमारी भी हो रही है, और कई बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण उनकी कम उम्र में ही मृत्यु भी हो जाती है,और भारत में इसके कारण मौत के आकड़े भी लगातार बढ़ रहे है, कहने के लिए तो यह सिर्फ आकड़े होते है पर एक घर से एक व्यक्ति की मौत भी उस परिवार को अत्याधिक पीड़ा देती है। नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी स्वभाव का होता है, उसे सिर्फ अपनी लत, अपनी खुशी से मतलब होता है, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी तो उसके परिवारजनों का क्या हाल होगा? नशे की लत के कारण कई बार वे चोरी, लूट और हिंसा जैसे कृत्य भी करते है। जहां देश के युवा से यह उम्मीद की जा रही रही थी कि वो देश के भविष्य को गौरवमयी बनाएगा ठीक इसके विपरीत आज का युवा देश को शर्मीदगी की ओर ले जा रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कही न कही सरकारी तंत्र भी इस अभिशाप का सहभागी है क्योंकि इससे उनकी भी रोजी रोटी चलती है। निस्संदेह यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह भी इस विषय पर ध्यान दे और समय समय पर आम जनमानस को इस हेतु सचेत करे, किन्तु युवा को स्वयं भी अपने भविष्य व साथ ही देश के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। कभी-कभी समाचार पत्र अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस विषय पर चिंतन करते है किन्तु सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी युवा शक्ति अपनी ताकत को समझे और न केवल अपने विकास मे सहायक हो वरन देश के विकास मे भी सहयोगी बने।

कलेक्टर ने आगनवाड़ी एवं स्कूलों का किया औचक निरीक्षण

ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, समाधान करने तत्काल संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर आज सुबह 8 बजे जिले के ग्राम बलारपुर पहुँचे और खेरा में बिखरी पड़ी ऐतिहासिक धरोहर मढ़ा का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की जल समस्या से अवगत कराने पर कलेक्टर ने जल निगम के अधिकारियों को तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। तदोपरांत कलेक्टर जनपद जबेरा अंतर्गत ग्राम पंचायत झरौली के आगनवाड़ी केंद्र एवं स्कूल का निरीक्षण किया, जहां उन्हें व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली, उन्होंने छात्रों से चर्चा की और पढ़ने के लिये प्रोत्साहित किया, उनकी नोट बुक देखी व पढ़ाई के टिप्स दिये। अपने भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम मुवार में राधा रमण जानकी मंदिर के प्राचीन ऐतेहासिक भवन का जायजा लिया।

उन्होंने झरौली में प्राचीन तालाब एवं मुआर में प्रसिद्व सिद्ध बाबा स्थल का जायजा लिया,जहां ग्रामीणों द्वारा पेड़ो की देखभाल

की जानकारी लगने पर कलेक्टर ने ग्रामीणों की प्रशंसा की। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या सुन उनका समाधान करने के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बनवार में सड़क किनारे एवं खुले में माँस-मछली की दुकान खुलने की शिकायत मिलने पर अधिकारियों को तत्काल सड़क किनारे एवं खुले में खुलने वाली माँस-मछली की दुकाने हटाने निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा आज छितरा, झरौली और मुआर गांव का निरीक्षण किया है। इन तीनों जगह पर दमोह की जो ऐतिहासिक और पुरातत्व की संपदा है, उसका भी जायजा लिया है और साथ में आंगनवाड़ी भवन, स्कूल भवन और मध्यान्ह भोजन के किचन शेड इसके अलावा पुरानी प्राचीन बावड़िया, इन सभी का निरीक्षण भी किया ।

कलेक्टर ने कहा ग्रामीणजनों ने जो समस्याएं बताई है उसके लिए तत्काल संबंधित अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिए गए हैं, वे अगले एक-दो दिन में संबंधित जगहों पर जाएंगे चीजों को देखेंगे और समस्याओं का निराकरण करेंगे। उन्होंने कहा पुरातत्व की जो संपदा है उसकी जानकारी हासिल हुई है, जिससे उसके संरक्षण के लिए काम किया जायेगा। झरौली में एक पुरातत्व महत्व की मूर्ति है, उसे जिला संग्रहालय में ले जाकर रखा जायेगा, वह मूर्ति अगले एक-दो दिन के अंदर संग्रहालय में स्थापित हो जाएगी, ताकि वहां पर उसकी प्रॉपर देखरेख हो सके। उन्होंने बताया लगातार गांव की समस्याओं को हल करने के लिए निरंतर काम किये जा रहे हैं।

पानी में उतराता मिला मास्टर ट्रेनर युवती का शव

5 दिनों से थी घर से लापता

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ शहडोल, पांच दिनों से लापता युवती का शव संदिग्ध अवस्था में सोन नदी में उतरता हुआ मिला है। ब्यौहारी में रहकर युवती मास्टर ट्रेनर का कार्य करती थी बीते दिनों वह घर से अचानक कहीं लापता हो गई थी, परिजनों ने मामले की शिकायत ब्यौहारी थाने में दर्ज कराई थी ब्यौहारी पुलिस ने गुम इंसान दर्ज कर युवती की तलाश शुरू की थी, जिसका शव पांच दिनों बाद देवलौंद थाना क्षेत्र के चचाई गांव में स्थित सोन नदी में मिला है। थाना प्रभारी डीके दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मवेशी चरा रहे एक व्यक्ति ने नदी

के किनारे शव देख मामले की जानकारी पुलिस को दी जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाया गया और पहचान के लिए पुलिस ने लग गई, कुछ घंटे के अंदर ही युवती की पहचान रीना द्विवेदी जिला उमरिया थाना पाली के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि रीना ब्यौहारी में रहकर मास्टर ट्रेनर का कार्य करती थी, बीते दिनों वह लापता हो गई थी, परिजनो ने गुम इंसान दर्ज कराया था ब्यौहारी पुलिस उसकी तलाश कर रही थी जिसका शव चचाई गांव में स्थित सोन नदी में पानी में उतारता मिला है पुलिस ने मामले पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या कर उसके शव को वहां फेंका गया है हालांकि पुलिस ने पूरे मामले पर बारीकी से पड़ताल शुरू की है।

डीएम ने जिला एवं महिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण

मरीजों से किया जाए मृदु व्यवहार, चिकित्सालय में मरीजों को न हो किसी प्रकार की असुविधा : डीएम मनीष बंसल

गौरव सिंघल । सिटी चीफ । सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने एसबीडी जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा चिकित्सालय के इमरजेन्सी वार्ड, ट्रामा सेन्टर, ए0टी0एफ0 वार्ड, आई0सी0यू0 वार्ड, रजिस्ट्रेशन काउन्टर, मेडिकल वार्ड, ओ0पी0डी0,कार्यालय, पैथोलोजी विभाग आदि का निरीक्षण किया। चिकित्सालय की समस्त चिकित्सीय एवं साफ-सफाई की व्यवस्था दुरूस्त पायी गयी। सभी चिकित्सक एवं स्टाफ अपने अपने डयूटी स्थल पर पूर्ण वेशभूषा में उपस्थित पाये गये। चिकित्सालय में आने वाले मरीजों से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि समय पर चिकित्सकों द्वारा राउण्ड लिया जा रहा है, इलाज बहुत अच्छा मिल रहा है एवं समय पर दवाईयां व इन्जेक्शन दिये जा रहे है। जिसकी जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा मुक्त कंठ से प्रशंसा की गयी। वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये बाहर पोल पर अतिरिक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने के निर्देश दिये।

डीएम मनीष बंसल ने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से वार्ता की एवं निर्देश दिए कि भर्ती मरीजों का बेहतर इलाज किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सभी चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर समय से उपस्थित होकर शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें ताकि रोगियों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित लाभ मिल सके। चिकित्सकीय परामर्श, पैथोलॉजी जांच, औषधियों का वितरण एवं देखरेख में किसी प्रकार की लापरवाही व कोताही न बरती जाए। मरीजों से मृदु व्यवहार किया जाए। पैरामेडिकल स्टाफ एवं सफाई कार्मिकों का मरीजों एवं तीमारदारों से अच्छा आचरण बर्ताव सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। किसी भी मरीज को बाहर से अल्ट्रासाउण्ड न कराना पडे। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में किसी मरीज एवं तीमारदार को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान प्रमुख अधीक्षक डॉ0 रामानन्द सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सम्मान समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को दिए गये 21 हजार रूपये, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल

सम्मान पाकर खिले मेधावियों के चेहरे, जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों ने किया छात्रों का उत्साहवर्धन

गौरव सिंघल । सिटी चीफ । सहारनपुर, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2024 में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जनपद के 20 मेधावी विद्यार्थियों को विकास भवन सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, महापौर डॉ0 अजय सिंह, विधायक नगर राजीव गुम्बर, विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा सम्मानित किया गया। लखनऊ में आयोजित विभिन्न बोर्डो के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का लाइव प्रसारण विकास भवन सभागार में उपस्थित मेधावी विद्यार्थियों, उनके माता-पिता अभिभावकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यो द्वारा देखा गया। प्रदेश स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं हेतु आभिभावकों के खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि का स्थानान्तरण, 165 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका इण्टर कालेज का लोकार्पण, 11 जनपदों डायट में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, ऑडिटोरियम तथा टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण का शिलान्यास, प्रदेश के 05 जनपदों के डायट हेतु निर्मित भवन का लोकापर्ण, एन0सी0आर0टी0 पैटर्न पर आधारित कक्षा-1 व 2 की नवीन नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में हाईस्कूल के परिक्षित तोमर, निखिल पंवार, पायल पाल, शाह आलम, रिया यादव, अरूषा, आरती, कशिश सैनी, वंशिका चौधरी एवं महिमा तथा इण्टरमीडिएट के यशवी कुश, तनु रानी, अंकिता, सिमरन, खुशी चौहान, अंशिका मन्धार, तनुजा, शानु कुमार, तनु काम्बोज, आर्यन कुमार को 21 हजार रूपये, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया तथा उनका उत्साह वर्धन करते हुए और अधिक मेहनत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक हर्ष देव स्वामी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ0 विनिता सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं छात्र-छात्रा उपस्थित रहे।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत बाटे गए टेबलेट

मदनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के 50 छात्रों को टैबलेट का वितरण किया गया

गौरव सिंघल । सिटी चीफ । सहारनपुर । देवबंद, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मदनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के 50 छात्रों को टैबलेट का वितरण किया गया। मदनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सत्र 2021-23 के छात्रों को टैबलेट वितरित करते हुए संस्था के प्रबंधक सुहेल सिद्दीकी ने प्रदेश सरकार की इस योजना की तारीफ की और छात्रों से टैबलेट का प्रयोग केवल शिक्षण कार्य के लिए ही करने का आह्वान किया। सचिव मोहम्मद अनस सिद्दीकी और फोरमैन सुरेंद्र सिंह ने छात्रों को बधाई दी और आधुनिक शिक्षा में आगे बढने की अपील की। समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने मदनी टेक्निकल ट्रेनिंग के महत्व को समझाया और मुस्लिम फंड

ट्रस्ट के तत्वाधान में चलने वाली आईटीआई, गर्ल्स इंटर कॉलेज और ड्राइविंग सेंटर सहित अन्य संस्थाओं की सेवाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नौशाद अहमद अंसारी, सभासद सैयद हारिस, वरिष्ठ समाजसेवी अशोक गुप्ता, डा. एसए अजीज, नागल बरांच मैनेजर साजिद हसन अंसारी, मा. शमीम किरतपुरी, भोपाल सिंह त्यागी, कलीम हाशमी, तनवीर अहमद, मोहम्मद शाकिर, सैयद नजम, अजयवीर, मुईद अख्तर, नाहिद, शकील, शहजाद समेत संस्था का स्टाफ मौजूद रहा।

उमरिया में बीते 24 घंटे में 18.5 मिमी वर्षा दर्ज

जानिए अन्य जिलों के हाल

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ । उमरिया, अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि जिले मे बीते 24 घंटे में 18.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई जिसमें बांधवगढ में 70.4 मिमी, मानपुर में 19.6 मिमी, पाली में 20.2 मिमी, नौरोजाबाद में 8.4 मिमी, चंदिया में 1.2 मिमी, करकेली में 11.2 मिमी, बिलासपुर मे 8.4 मिमी वर्षा शामिल है। जिले में 1 जून से लेकर 30 जून तक 46.3 मिमी वर्षा रिकार्ड गई है जिसमें बांधवगढ में 103.4 मिमी, मानपुर में 48मिमी, पाली में 40 मिमी, नौरोजाबाद में 79.6 मिमी, चंदिया में 19.4 मिमी, करकेली में 24.6 मिमी, बिलासपुर मे 19 मिमी वर्षा शामिल है । जबकि गत वर्ष इसी अवधि तक कुल 195.3 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई थी जिसमें बांधवगढ में 254.3 मिमी, मानपुर में 184.6 मिमी, पाली में 260 मिमी, नौरोजाबाद में 198.2 मिमी, चंदिया में 189.4 मिमी, करकेली में 98. 5 मिमी, बिलासपुर मे 182.4 मिमी वर्षा शामिल है ।

बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को मिला एनक्यूएएस प्रमाणीकरण

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमएचओ को दिया प्रशस्ति पत्र

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ । उमरिया, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण तथा उर्वरक और रसायन राज्य मंत्री माननीया श्रीमती अनुप्रिया पटेल तथा केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एव केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्रताप राव जाधव के कर कमलों के द्वारा उमारिया जिले की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली का एनक्यू एएस प्रमाणीकरण 95 प्रतिशत बेहतर स्वास्थ्य गुणवत्ता के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।राजधानी नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में उमरिया जिले से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस बी चौधरी, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सी के जैन तथा नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती रूपा कुशवाहा कार्यक्रम में नई दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रीगणो के हाथों यह सम्मान प्राप्त किया है।बताया गया कि उमरिया जिले के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसिंहपुर पाली का बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और गुणवत्ता के लिए छफौ के द्वारा प्रमाणीकरण किया गया था, जिसके चलते जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया और उनकी टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रशस्ति पत्र मिलने पर अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर वीके जैन सहित अन्य डॉक्टर, नर्स और उनके पूरे स्टाफ को इसका पूरा योगदान जाता है जिनकी मेहनत और प्रयास के कारण यह संभव हो सका है।

शहडोल कलेक्टर तरुण भटनागर ने जारी किया आदेश अब नदियों से रेत उत्खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ शहडोल, कलेक्टर तरुण भटनागर ने शहडोल जिले की संचालित रेत खदानों में नदी से रेत का उत्खनन 30 जून से दिनांक 1 अक्टूबर 2024 तक के लिये रेत उत्खनन कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नागपुर के निर्देश के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्षा ऋतु के लिए मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के द्वारा रेत खदान 15 जून से 01 अक्टूबर तक तक रेत (बालू) के उत्खनन पर रोक लगाने के संबंध में स्थानीय मौसम परिवर्तन के आधार पर उक्त निर्धारित वर्षाकाल अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है। जिले में मानसून दिनांक 30.06.2024 तक सक्रिय हो सकता है। शहडोल जिले की संचालित रेत खदानों में नदी से रेत का उत्खनन दिनांक 30 जून से दिनांक 1 अक्टूबर 2024 तक के लिये मानसून सत्र मान्य किया जाता है। प्रश्नाधीन अवधि के दौरान शहडोल जिले में स्थित नदियों से रेत उत्खनन कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है।

13 वर्ष बीते कोयलांचल को एसडीएम कोर्ट नहीं हुआ नसीब

विकास का खोखला दावा महज ठगा गया कोयलांचल - शैलेन्द्र श्रीवास्तव

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ

यूँ तो अब जनहित की बात करना तो नेताओ का काम नहीं रहा किसी सिम्बल और पार्टी के टैग पर जीतते और हारते जनप्रतिनिधियों को अब जनता के दु:ख दर्द से कोई वास्ता रह नहीं गया, जिसके चलते नि:शुल्क मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में लगातार सेंध लगाई जा रही है, अब तो जनता ने भी धरती के इस जीव की परिक्रमा करना बंद ही कर चुके है, अब न तो जनता का कोई जनप्रतिनिधि रहनुमा बने ऐसा किसी को रत्ती भर का यकीं नहीं है, बावजूद जिले के कोयलांचल अंतर्गत एक आवाज जनहित में बुलंद किये जाने की सूचना मिल रही है यह ठीक वैसा है जैसा की मुर्दो के शहर में कोई जिन्दा तो है जब भी मुँह खोलता है कितनो की पोल खोल देता है।

शहडोल, जिले की ऊर्जा नगरी जो प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका मूल क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का टोटा पड़ा हुआ है, और पूरा का पूरा यह कोयलांचल विकास की बाट जोहता नज़र आ रहा है यहा की जनता को केवल मतदान के वक़्त याद किया जाता है फिर पांच सालो तक माननीय नजरबंद से हो जाते है, इस बात को पूरी प्रमुखता से उठाते हुए जनता के मसीहा शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है की इस तरह स्थानीय जनता सिर्फ़ और सिर्फ़ ठगा रह जाता है, ना कोई नया उँग ना कोई नया महाविलय ना तो चिकित्सा सुविधाओं में कोई इज़ाफा और तो और 13 वर्ष बीत गए बुढ़ार को तहसील का दर्जा मिले हुए पर आज तक ना तो एसडीएम कोर्ट प्रारंभ हो सका ना ही रजिस्ट्री की सुविधा प्रारंभ हो सकी। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं की स्थिति, आज भी शिक्षा का स्तर वहीं का वहीं, नए महाविलय खुलने तो दूर जो एक मात्र शासकीय महाविलय है उसके भी पूर्व में संचालित कई पाठ्यक्रम अब बंद किए जा चुके हैं। जहां तक बात चिकित्सा सुविधाओं की है तो कल भी हमारे यहाँ के अस्पताल सिर्फ़ रेफ़र सेंटर थे आज भी वही स्थिति बरकरार है।

खनिज सम्पदा की खुली लूट.....

रोज़गार की तो बात करना ही बेमानी है जब पकौड़े तलना ही रोज़गार हो चुका है तो फिर शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इस बात के भी कोई मायने नहीं है कि संपूर्ण कोयलांचल क्षेत्र खनिज सम्पदा से भरा हुआ है कोयला और रेत दोनों प्रचुर मात्रा में है लेकिन पिछले तीन चार दशकों से ना तो कोई नया उँग स्थापित हो सका ना ही इस खनिज संपदा की लूट कम हो सकी, कोयला और रेत का अवैध कारोबार ज़रूर दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ता चला गया। अवैध खनन और रेत माफियाओं की तो हमेशा से बल्ले बल्ले रही, इसी खनन और रेत माफिया ने राजनीति में भी अपनी जड़े अब हर दल में इतनी गहराई तक जमा ली हैं कि राजनीति भी अब इनकी चौखट की सिर्फ़ गुलाम बन कर रह गई है

ऐसा भी नहीं है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, हुआ पर सिर्फ़ वही निर्माण कार्य हुआ जिससे मोटी कमाई की जा सके, बुढ़ार की बदहाल मॉडल रोड और नगरपालिका परिषद धनपुरी का एलईडी लाइट घोटाला इसका जीता जागता उदाहरण है।

वर्षों बाद जब मीथेन गैस मिली तो लगा कि अब क्षेत्र में नई रिफ़ाइनरी स्थापित होगी और हज़ारो लोगों को नया रोज़गार मिल सकेगा, रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट आया और मीथेन पाइप लाइन से कहीं और भेज दी गई, और लोगों की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं।

नहीं टिकते ईमानदार अफसर.....

ना जाने क्यों किसी तेज तर्रार अधिकारी की इस ज़िले में पदुस्थापना ही नहीं की जाती, पिछले कई दशकों में बिरले ही अधिकारी ऐसे आये जिनके आने से कोयलांचल समेत पूरे ज़िले को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई पड़ी, पर चाहे वो निडर आईएएस अधिकारी लोकेश जांगीड रहे हो या सबके चहेते ईमानदार आईपीएस अधिकारी अवधेश गोस्वामी, इनमें से कोई भी इस ज़िले में ज़्यादा दिन तक ष्ठक नहीं पाया।

माफिया तो नहीं लगा रहा अड़ंगा....

13 वर्ष बीत गए बुढ़ार को तहसील का दर्जा मिले हुए पर आज तक ना तो एसडीएम कोर्ट प्रारंभ हो सका ना ही रजिस्ट्री की सुविधा प्रारंभ हो सकी, हैरानी की बात तो ये है कि जब जनता ने आवाज़ उठाई तो एक नहीं बल्कि दो दो बार एसडीएम कोर्ट का संचालन प्रारंभ हुआ पर सिर्फ़ एक ही दिन के लिए, फूल और गुलदस्तों के मुरझाने से पहले ही दूसरे ही दिन कोर्ट का संचालन किसी ना किसी कारण से बंद कर दिया गया, पता नहीं वे कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते कि बुढ़ार में एसडीएम कोर्ट प्रारंभ हो। हो सकता है कि ये वही खनन या रेत माफिया हो जिसको डर हो कि उनके अवैध उत्खनन में अड़चन ना आने लगे, पर इससे भी कहीं ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि दोनों बार इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बिलकुल मौन रहे।

कनाडा के सदन में आतंकी निज्जर को श्रद्धांजलि देने के मामले में पी.एम. ट्रूडो ने लिया संज्ञान

नेशनल डेस्क: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यालय ने सरी स्थित रेडियो इंडिया के प्रबंध निदेशक मनिंदर गिल के उस पत्र का संज्ञान ले लिया है, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन में स्पीकर द्वारा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि देने का विरोध किया गया है। निज्जर की सरी में बीते साल एक गोलीबारी की घटना में मौत हो गई थी। मनिंदर गिल के पत्र का जबाव देते हुए ट्रूडो के कार्यालय के कार्यकारी पत्राचार अधिकारी जे.गेंज ने आश्वासन दिया है कि उनके पत्र में की गई टिप्पणियों की समीक्षा की गई है और इसे अब डोमिनिक लेब्लांक, सार्वजनिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और अंतर-सरकारी मामलों के मंत्री को उनकी जानकारी और विचार के लिए भेजा जाएगा। जे. गेंज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामला संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद भी किया है।

गिल ने पत्र में क्या लिखा?

रेडियो इंडिया के प्रबंध निदेशक मनिंदर गिल ने जस्टिन ट्रूडो को लिखे पत्र में अपने विचार रखते हुए कहा था कि 23 जून हर कनाडाई के लिए बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम इस दिन उन 329 लोगों को याद करते हैं जिन्होंने ने कनिष्क बम विस्फोट में अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने लिखा कि विमानन इतिहास में सबसे भयानक आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार चरमपंथी विचारधारा को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वैधता प्रदान की गई। बीते 19 जून हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर ने सदन के सदस्यों से आग्रह किया कि जिस हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल सरी में हत्या कर दी गई थी, उसकी याद में खड़े होकर मौन रखा जाए। गिल ने इस घटनाक्रम पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हरदीप निज्जर की जघन्य हत्या अक्षम्य है और इस अपराध के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हालांकि हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मान प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति का चरित्र बेदाग होना चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स एक राष्ट्र के रूप में कनाडा और क्राउन की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है।

निज्जर के आतंकी संबंधों का जिक्र

ग्लोब एंड मेल में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाले देते हुए मनिंदर गिल ने ट्रूडो को लिखा कि इस लेख में कहा गया है कि हरदीप निज्जर लोगों से हथियार उठाने का आह्वान किया और उन लोगों का मजाक उड़ाया जो शांतिपूर्ण सक्रियता में विश्वास करते थे। लेख में आगे बताया गया है कि वह व्यक्ति चरमपंथ में डूबा हुआ था। उसके आतंकवादियों और सामूहिक हत्यारों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। उसे पाकिस्तान की अपनी एक कथित यात्रा में ए.के.47 असॉल्ट राइफल चलाते हुए भी देखा जा सकता है। यह भी आरोप है कि वह नकली पासपोर्ट पर कनाडा आया था। गिल ने लिखा कि एक कनाडाई के रूप में मुझे यह जानकर दुख होता है कि ऐसे व्यक्ति को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में सम्मानित किया गया है।

निज्जर को सम्मानित करने की प्रक्रिया पर सवाल

उन्होंने पत्र में कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में एक नाजी को सम्मानित करने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में आमंत्रित या सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों की जांच करने के लिए किसी प्रकार की प्रक्रिया विकसित की जाएगी, लेकिन इस घटनाक्रम से विपरीत संकेत मिल रहे हैं। रेडियो इंडिया के प्रबंध निदेशक ने कहा है कि क्या ट्रूडो सभी कनाडाई लोगों को यह बताना चाहेंगे, कि इस निर्णय तक पहुंचने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। इस कदम से पहले किस तरह की चर्चा हुई और यह समझौता कैसे हुआ? उन्होंने पत्र में लिखा कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार को जवाबदेह ठहराएं और जनहित की रक्षा करें।

गाजा में बढ़ा फिलिस्तीनियों के मारे जाने का आंकड़ा, अब तक 37,877 लोगों की मौत

गाजा: गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली हमलों में फिलिस्तीनी मृतकों की संख्या बढ़कर 37,877 हो गई है। गाजा स्थित स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायली सेना की कार्रवाई में 43 लोग मारे गए और 111 अन्य घायल हो गए। अक्टूबर 2023 में फिलिस्तीनी-इजरायल संघर्ष शुरू होने के बाद से कुल मृतकों की संख्या 37,877 और घायलों की संख्या 86,969 हो गई। बयान के अनुसार कई पीड़ितों के शव अभी भी मलबे के नीचे या सड़कों पर पड़े हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को एक अलग बयान में चेतावनी दी कि जनरेटर चलाने के लिए आवश्यक ईंधन की कमी के कारण गाजा पट्टी में शेष अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और ऑक्सीजन स्टेशन 48 घंटे के भीतर बंद हो जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि इज़रायल ने सात अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इज़रायली सीमा के माध्यम से हमास के हमले का बदला लेने के लिए गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, जिसके दौरान लगभग 1,200 लोग मारे गए और लगभग 250 अन्य को बंधक बना लिया गया।

फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मैंक्रों को झटका, दक्षिणपंथी सरकार के पूरे आसार

इंटरनेशनल डेस्क: फ्रांस के ससंदीय चुनाव के पहले दौर में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रों की पार्टी पीछे हो गई है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक मरीन ले पेन की दक्षिणपंथी नेशनल रैली (आरएन) पार्टी ने बढ़त बना ली है। जिसके कारण मैंक्रों की पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई है।

आईपीएसओएस के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक नेशनल रैली (आरएन) के नेतृत्व वाला धुर दक्षिणपंथी गठबंधन 34 फीसदी वोट के साथ पहले स्थान पर है, जबकि वामपंथी गठबंधन 28.1 फीसदी वोट के साथ दूसरे स्थान पर है, वहीं मैंक्रों की पार्टी 20.3 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर चल रही है।

एग्जिट पोल में किसी को भी बहुमत नहीं

सीएनएन रिपोर्ट के मुताबिक एग्जिट पोल में अगले रविवार को दूसरे दौर के मतदान के बाद 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में आरएन 230 से 280 सीटें जीत सकती है, जो कि पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 289 सीटों से कम है। वहीं वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट (एनएफपी) को 125 से 165 सीटों का अनुमान, जबकि मैंक्रों के एन्सेम्बल और उसके सहयोगी 70 से 100 सीटें जीत सकते हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर ने कतर के PM से की मुलाकात

द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा

दोहा: विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की जिसमें राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों से लोगों के संबंध से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया गया। यहां एक दिवसीय यात्रा के तहत पहुंचे जयशंकर ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी शेख मोहम्मद के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। शेख मोहम्मद के पास विदेश मंत्री का भी प्रभार है।

जयशंकर ने 'एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज दोपहर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थानी से मिलकर खुशी हुई। महामहिम अमीर तक उनको प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से दी गईं शुभकामनाएं पहुंचाई। उन्होंने कहा, राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों से लोगों के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। गाजा स्थिति पर उनकी साझा अंतर्दृष्टि की सराहना करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा, हम भारत-कतर संबंधों को और बेहतर बनाने तथा आपसी हितों के मुद्दों पर निरंतर बातचीत की आशा करते हैं। कतर की समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक, बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों नेताओं ने साझा हितों के कई मुद्दों के अलावा दोनों देशों के बीच सहयोग संबंधों और उन्हें समर्थन देने तथा विकसित करने के तौर-तरीकों की समीक्षा की। जयशंकर की यह यात्रा भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को कतर द्वारा रिहा किये जाने के साढ़े चार महीने बाद हो रही है, जिन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार होने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। प्रोटोकॉल प्रमुख इब्राहिम फखरू ने विदेश मंत्री जयशंकर का हवाई अड्डे पर स्वागत किया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को नयी दिल्ली में कहा, विदेश मंत्री की यह यात्रा दोनों देशों को राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों के साथ-साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने में सक्षम बनाएगी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 से 15 फरवरी तक कतर दौरे के दौरान अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से चर्चा की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

नाइजीरिया में महिला आत्मघाती हमलावरों ने शादी समारोह व अंतिम संस्कार कार्यक्रम में किए अटैक, 18 लोगों की मौत

इंटरनेशनल डेस्क: उत्तरी नाइजीरिया में महिला आत्मघाती हमलावरों ने एक विवाह समारोह, अंतिम संस्कार कार्यक्रम और एक अस्पताल को निशाना बनाकर समन्वित हमले किए जिनमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय प्राधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। बोर्नो राज्य में हुए इन हमलों की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। यह राज्य बोको हराम के उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चरमपंथी समूह आत्मघाती बम विस्फोटों में पहले भी महिलाओं और लड़कियों का इस्तेमाल कर चुका है जिससे यह संदेह पैदा होता है कि इनमें से कुछ हमलावर उन स्कूली बच्चों समेत हजारों लोगों में से हैं जिन्हें आतंकवादियों ने पिछले कुछ सालों में अगवा किया है। बोर्नो राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के महानिदेशक बार्किंडो सैदु ने संवाददाताओं को बताया कि एक आत्मघाती हमलावर ने उत्तरपूर्वी शहर ग्वोजा में एक विवाह समारोह के दौरान विस्फोट किया। सैदु ने कहा, कुछ ही मिनट बाद जनरल अस्पताल के पास एक और धमाका हुआ और अंतिम संस्कार के दौरान तीसरा हमला हुआ। उन्होंने बताया कि मृतकों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। सैदु ने कहा कि कम से कम 30 अन्य घायल हुए हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टीनुबू ने एक बयान में इन हमलों को आतंक की हताशाजनक हरकत बताया है। बोको हराम की एक शाखा इस्लामिक स्टेट समूह से संबद्ध है और यह नाइजीरिया में इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता है। अधिकारियों ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है।

स्कूल टीचर नाबालिग छात्र से करती थी सेक्स, पोल खुलने पर...

नेशनल डेस्क - अधिकारियों ने बताया कि न्यू जर्सी के फ्रीहोल्ड इंटरमीडिएट स्कूल में 43 वर्षीय टीचर को नाबालिग छात्र के साथ कथित यौन संबंध के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मोनमाउथ काउंटी के अभियोक्ता रेमंड एस सैंटियागो के अनुसार एलिसन हैवमैन-नीड्राच पर प्रथम-डिग्री गंभीर यौन उत्पीड़न और एक बच्चे के कल्याण को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। जांच के अनुसार एलिसन ने कथित तौर पर इस साल की शुरुआत में एक छात्र का यौन शोषण करना शुरू कर दिया था। हालांकि, अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि यह कैसे सामने आया या उसने कितनी बार छात्र पर हमला किया। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि छात्र की उम्र का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र पढ़ते हैं। वह वर्तमान में मोनमाउथ काउंटी जेल में हिरासत में सुनवाई के लिए बंद है। यह पता लगाने के लिए सुनवाई की जाएगी कि क्या वह मुकदमे की प्रतीक्षा करते समय गिरफ्तारी के तहत रहेगी। अभियोक्ता कार्यालय उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से आगे आने का आग्रह कर रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है, हैवमैन-नीड्राच की गतिविधियों के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से 800-533-7443 पर स्ष्टक्क्ह जासूस डॉन कोरेया से संपर्क करने का आग्रह किया जा रहा है। आरोप टीचर की प्रोफाइल के अनुसार, हैवमैन-नीड्राच मार्च 2022 से फ़्रीहोल्ड इंटरमीडिएट स्कूल में एक विशेष शिक्षा शिक्षिका हैं और 2008 से कई स्कूलों में अध्यापन और स्थानापन्न अध्यापन का उनका इतिहास रहा है। वह खुद को एक उत्साही, परिणाम-उन्मुख और ईमानदार शिक्षिका के रूप में वर्णित करती हैं। संतुलित और सक्षम, वह प्रदर्शन-संचालित वातावरण में पनपती हैं। इस बीच, शिक्षक के वकील ने एक बयान में कहा कि वह अपनी बेगुनाही बरकरार रखती है और आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

नेपाल में मुस्लिमों ने हिन्दुओं के गांव का नाम बदल कर रख दिया 'इस्लाम नगर', हिंदू युवकों को भी पीटा

काठमांडू: नेपाल के रौतहट जिले में साम्प्रदायिक तनाव की घटना सामने आई है। यहां एक सप्ताह पहले मुस्लिमों ने एक गांव का नाम इस्लाम नगर रखकर इससे बोर्ड लगवा दिया। हिन्दुओं को इसका पता चला तो वे भड़क गए और इस बोर्ड को उखाड़ फेंका। इसके बाद मुस्लिमों ने हिन्दू समुदाय के कुछ युवाओं की पिटाई कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना 23 जून की बताई जा रही है। मामला रौतहट जिले के गरुडा नगरपालिका वॉर्ड नंबर 6 का है। यहाँ के गाँव पोठियाही में सप्ताह भर पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक चौराहे पर इस्लाम नगर का बोर्ड लगा दिया। यह बोर्ड बाकायदा हरे रंग में रंगा गया था। बोर्ड के ऊपर अरबी और उर्दू भाषा में कई शब्द लिख दिए गए थे। बोर्ड के ऊपर दोनों तरफ इस्लामी इबादतगाहों की तस्वीरें भी छाप दी गई थीं। यहाँ पर खड़े होकर एक मुस्लिम बुजुर्ग ने एक सेल्फी भी ली थी, बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कहा जा रहा है कि स्थानीय मुस्लिम इस जगह को अपनी तरफ से इस्लाम नगर कह कर बुलाने भी लगे थे। घटना के दिन मौके पर पहुँचकर मुस्लिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदू पक्ष ने नेपाल प्रशासन पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया है। नेपाल के संगठन 'हिन्दू सम्राट सेना' के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि पोठियाही गाँव में मुस्लिमों के महज 10 घर हैं, जो कि गाँव की कुल आबादी का महज 4त्न है। इसके बावजूद इन्होंने पूरे पोठियाही गाँव के नाम को बदलने की साजिश रच डाली ।

23 जून को हिन्दू सम्राट सेना के सदस्यों ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर इस्लाम नगर वाले इस बोर्ड को उखाड़ दिया। उन्होंने कहा कि उस दौरान मुस्लिम पक्ष के लोग खामोश रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे। 25 जून की रात को तीन हिन्दू युवक चौराहे से गुजर रहे थे। इस दौरान उनको लगभग एक दर्जन मुस्लिमों ने घेर लिया और उन पर इस्लाम नगर वाला बोर्ड उखाड़ने का आरोप लगाकर पहले गंदी-गंदी गालियाँ दी गईं और बाद में उनकी पिटाई कर दी । इस हमले में हिंदू समुदाय के युवक बुरी तरह घायल हो गए।

हिंसक भीड़ को चाँद दीवान, रफीक, सिराजुल और मंजूर आदि लोग लीड कर रहे थे। इस हमले की जानकारी मिलते ही आसपास के हिन्दू नाराज हो गए। हिन्दुओं ने एकजुट होकर इस हमले का विरोध किया। इस बीच मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुँच गए। हिंदू पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने हमला करने वाले मुस्लिमों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, उन मुस्लिम परिवारों को ही पुलिस ने बजाय सुरक्षा दे दी, जिन्होंने हमला किया था। नेपाल प्रशासन इस घटना को आपसी विवाद बताकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में कोई साम्प्रदायिक एंगल नहीं है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569